

Lok Shakti

लोक शक्ति



सनातन से विश्व कल्याण
का मार्ग दिखाता भारत

रोज करें 5 एक्सरसाइज

आर्म पर जमा फैट हो जाएगा गायब



उम्र बढ़ने के साथ शरीर पर चर्बी जमना महिलाओं के लिए एक बड़ी समस्या होती है. बढ़ते वजन के कारण वे अपने पसंदीदा कपड़े नहीं पहन पातीं और जल्दी थकान भी महसूस करने लगती हैं. खासतौर पर महिलाओं के लिए अपने हाथ के लटकते फैट को कम करना सबसे बड़ा काम लगता है. कई महिलाओं के पास जिम जाने का वक्त नहीं होता है और ना ही घर में किसी तरह का एक्सरसाइज मशीन ही होता है. ऐसे में निराश होने की जरूरत नहीं, आप घर पर कुछ सिंपल एक्सरसाइज की मदद से अपने हाथों को टोन्ड और फिट बना सकती हैं.

पहली एक्सरसाइज – सबसे पहले आप सीधा खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों को बाँड़ी से करीब एक बिल्ले की दूरी पर हटाकर रखें. अब हाथों को एक साथ ऊपर ले जाएं और ताली बजाकर दोबारा पहले पोजीशन में आ जाएं. ऐसा एक मिनट तक करें.

दूसरी एक्सरसाइज – दोनों हाथों की कोहनियों को 90 डिग्री पर फोल्ड करें. अब मुट्ठी बांधकर हाथों को एक बार सामने लाएं और एक दूसरे से सटाएं और फिर पहले पोजीशन में आ जाएं. ऐसा आप लगातार एक मिनट तक करें फिर रिलैक्स करें.

तीसरी एक्सरसाइज – अब दोनों हाथों को सीधा करें और उंगलियों को सीधा करते हुए पीछे नीचे की तरफ सीधा करें. अब तीन बार दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए आगे सीने के पास आगे पीछे करें और फिर चार बोलते हुए नीचे पीछे की तरफ झटककर ले

जाएं. ऐसा एक मिनट तक करें.

चौथी एक्सरसाइज – अब दोनों हाथों को दोनों तरफ पंख की तरह सीधा कर लें और एक बार उठाएं और एक बार थोड़ा नीचे की तरफ बेन्ड करें. ऐसा आप 1 मिनट तक करें.

पांचवीं एक्सरसाइज – अब दोनों हाथों को कोहनियों से बेन्ड करें और आकाश की तरफ प्वाइंट करें. अब हाथ को एक मिनट तक ऊपर नीचे करें. हफ्तेभर में आपके हाथ टोन्ड होने शुरू हो जाएंगे. धीरे धीरे आप अपनी क्षमता के अनुसार व्यायाम के समय को बढ़ाकर 3 से 4 मिनट तक ले जाएं. आप चाहें तो दोनों हाथों में पानी के बोतलों को लेकर भी ऐसा कर सकती हैं.

EDITOR-IN-CHIEF Premendra Agrawal
EXECUTIVE EDITOR Rajesh Agrawal
MANAGING EDITOR Mr. Subhash
GROUP CREATIVE EDITOR Anjana
CHIEF ART DIRECTOR Deepika
FOREIGN EDITOR(US) Jamuna
CHIEF DESIGNER Vineeta Agrawal

RNI: CHHBIL/2020/80139

BUSINESS OFFICE

CHIEF EXECUTING OFFICER Satyabhama Agrawal

GENERAL MANAGER Vinod Agrawal

PUBLISHER Premendra Agrawal

MARKETING DIRECTOR Mr. Subhash

PHOTOGRAPHER Pawan Kumar

DIGITAL Tejas Agrawal

CHIEF PHOTO RESEARCHER Krishna

HEAD OFFICE

LOK SHAKTI, Agrasen Marg
Ramsagarpara, Raipur,
Chhattisgarh - 492001 (INDIA)
Whatsapp : 9926022174
e-mail: lokshakti.india@gmail.com

Printed and published by Premendra Agrawal

Editor: Premendra Agrawal.

Printed at Commercial Services

Agrasen Marg, Ramsagarpara, Raipur (CG).

Published from LOK SHAKTI, Agrasen Marg

Ramsagarpara, Raipur (CG).

YEAR : 03; ISSUE : 12

Published for the Month of September , 2023

Released on September , 2023

Total no. of pages 32, including Covers



SCAN AND SHARE

Read Lok Shakti on your
smart phone instantly.
Point your phone's scanner on the
code above and align it in the frame.
You will be guided instantly
to www.lokshakti.in.

NAVIGATOR

05

COVER STORY

विश्व कल्याण का मंत्र

07	भारत का कद बढ़ा
08	इकोनॉमिक कॉरिडोर
09	मानव-केंद्रित वैश्वीकरण

10	90 हजार गांवों में संपत्ति कार्ड तैयार	23	ECONOMY
11	MP सरकार शुरू कर रही नई योजना	24	पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टरप्लान
12	Chhattigarh	25	देश भर के शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान
14	G20	26	Konark Temple
15	UP	27	आतंकियों की संपत्ति जब्त
20	शिव-नटराज	28	विश्व बैंक द्वारा तैयार जी20 दस्तावेज़
21	Morocco Earthquake	29	रसोई गैस उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत

Message from Executive Editor's

We welcome you to our monthly magazine! You will find contents from across sectors including Politics, Education, Health, Economics among others. We have a great emphasis on Opinions, News & Analysis along with hints and Events from across the globe.

We want our publication to be valuable for you so please, do share your feedback and suggestions to help us improve. We have signed you up for our monthly magazine in the hopes that you will find great value in its content. Lok Shakti's publication comes with promise of great growth and change.

With each passing year, Interests and taste change, economies and leadership rise and fall, children age and grow ... in truth it sees perhaps the most change of all.

...The media is simply a tool, and it's our job to help you use it in the way that's right for you as well as for the country and the world.

Sincerely,
Rajesh Agrawal
Executive Editor

सनातन मंत्र से विश्व कल्याण का मार्ग दिखाता भारत

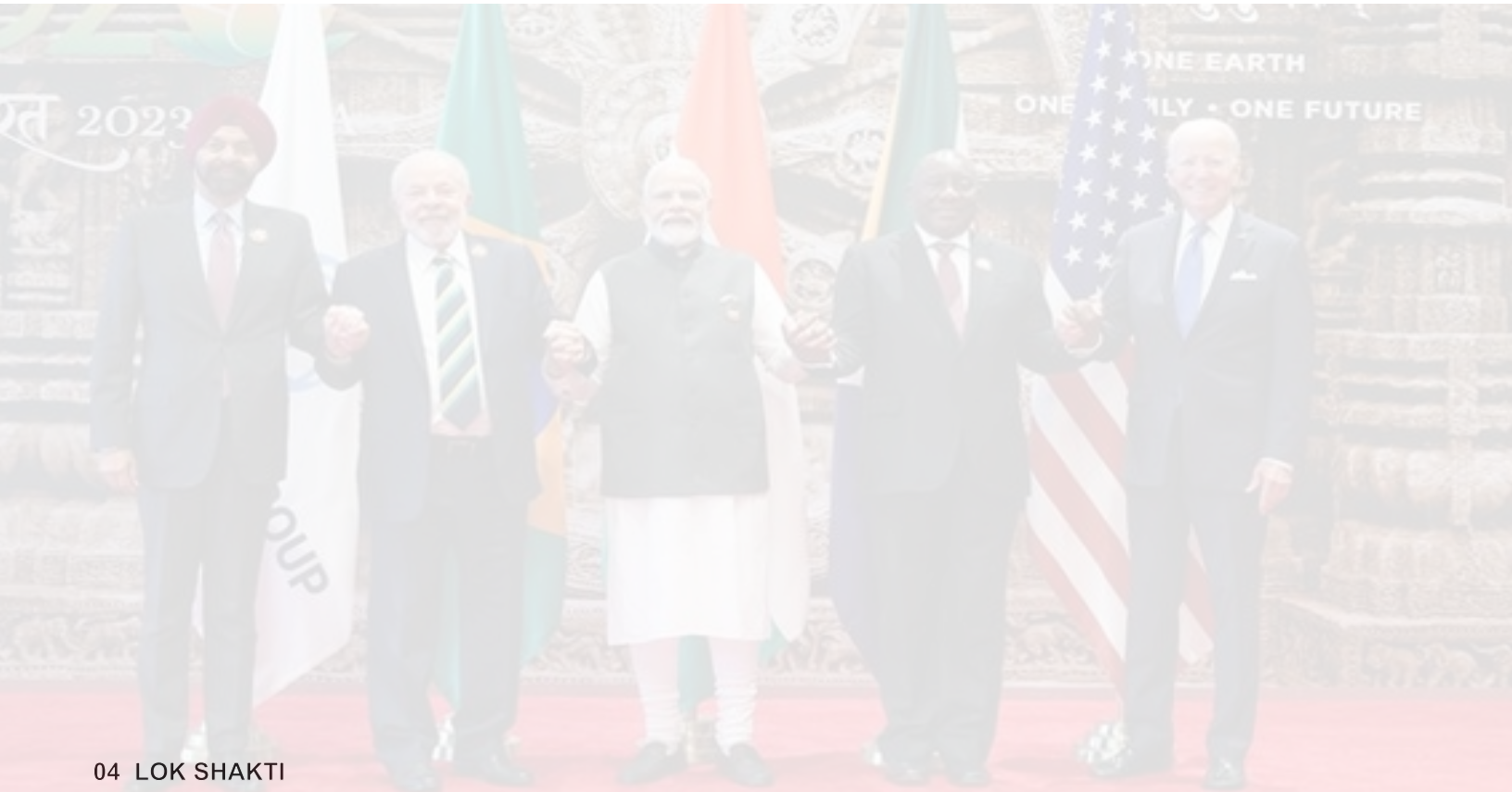
आजादी के बाद पहली बार देश में जी-20 शिखर सम्मेलन जैसा बड़ा आयोजन हो रहा है। इस महासम्मेलन में चारों तरफ सनातन संस्कृति की छाया है जिसे देखकर हर भारतवासी का दिल गौरव से भर उठा। यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में संभव हो रहा है। पिछले नौ साल से देश में सनातन गौरव की पुनः स्थापना में दिन-रात जुटे पीएम मोदी ने जी-20 जैसे बड़े आयोजन में सनातन संस्कृति का झंडा बुलंद करके भारत माता का मान बढ़ाया है। इन सुखद दृश्यों को देखकर आज हर भारतवासी भावविभोर है। यह कहा जा सकता है कि सनातन की धरोहर को एक सन्यासी ही संजो सकता है। जी-20 में भारत की प्राचीनता और आधुनिकता का अद्भुत संगम दुनिया देख रही है। भारत के सांस्कृतिक दूत और सनातन के सच्चे सेवक पीएम मोदी के विजन से जी-20 आयोजन स्थल सनातन संस्कृति से रचा-बसा नजर आया। नटराज की प्रतिमा, कोणार्क चक्र, रामायण, महाभारत, विष्णु अवतार के दर्शन, गीता ऐप के जरिये जीवन दर्शन आदि सनातन प्रतीक देखकर विदेशी मेहमान भी मोहित हुए बिना नहीं रह सके।

देश की राजधानी दिल्ली में 9 सितंबर 2023 को जी-20 शिखर सम्मेलन का आगाज हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान के भारत मंडपम में सभी जी-20 नेताओं और प्रतिनिधियों का

जिस स्थान पर हाथ मिलाकर स्वागत किया, वहां पीछे एक बड़ा-सा चक्र बना हुआ था। ये बेहद खास चक्र है, जिसका नाम 'कोणार्क चक्र' है। ओडिशा के कोणार्क चक्र को 13वीं शताब्दी के दौरान राजा नरसिंहादेव-प्रथम के शासनकाल में बनाया गया था। कोणार्क चक्र वही चक्र है, जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में नजर आता है। 24 तीलियों वाले कोणार्क चक्र को भारत के राष्ट्रीय ध्वज में रूपांतरित किया गया, जो भारत के प्राचीन ज्ञान, उन्नत सभ्यता और वास्तुशिल्प उत्कृष्टता का प्रतीक है। समय हमेशा एक सा नहीं रहता, ये बदलता रहता है। कोणार्क चक्र इस समय का ही प्रतीक है, जो कालचक्र के साथ-साथ प्रगति और परिवर्तन को दर्शाता है।

दिल्ली के भारत मंडपम में जी-20 शिखर सम्मेलन के पहले सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपनी बात शुरू की वह भी सनातन संस्कृति का जयघोष ही था। पीएम मोदी ने कहा कि ढाई हजार साल पहले भारत की धरती ने मानवता के कल्याण का संदेश पूरी दुनिया को दिया था। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा देने वाला है। पीएम मोदी ने भारतीय संस्कृति पर कहा- इस समय जिस स्थान पर हम एकत्रित हैं, यहां से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर लगभग ढाई हजार साल पुराना एक स्तंभ लगा हुआ है। इस स्तंभ पर प्राकृत भाषा में लिखा है- "हेवम लोकसा हितमुखे ति, अथ इयम नातिसु हेवम"। अर्थात्, मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। ढाई हजार साल पहले, भारत की भूमि ने, यह संदेश पूरे विश्व को दिया था। आइए, इस संदेश को याद कर, इस G-20 समिट का हम आरम्भ करें।

दिल्ली में जी-20 शिखर सम्मेलन इस बार सनातन संस्कृति की छाया में हो रहा है। आजादी के बाद पहली बार देश में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। इसी भाव को दृष्टिगत रखते हुए शिखर सम्मेलन स्थल पर भगवान शिव की 28 फीट ऊंची 'नटराज' प्रतिमा को प्रतीक रूप में स्थापित किया गया है। इस प्रतिमा में शिव के तीन प्रतीक-रूप परिलक्षित हैं। ये उनकी सृजन यानी कल्याण और संहार अर्थात् विनाश की ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतीक हैं। अष्टधातु की यह प्रतिमा प्रगति मैदान में 'भारत मंडपम' के द्वार पर लगाई गई है। इस प्रतिमा की आत्मा में सार्वभौमिक स्तर पर सर्व-कल्याण का संदेश अंतर्निहित है। इसे देखकर विदेशी मेहमान भी मोहित हो गए।



विश्व कल्याण का मंत्र



पीएम मोदी के दिए 'वसुधैव कुटुंबकम्' का मंत्र जी-20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान यह विचार मानव केंद्रित प्रगति के आह्वान के रूप में प्रकट हुआ है। हम एक धरती के रूप में मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक साथ आ रहे हैं। जिससे सब एक-दूसरे के सहयोगी बने रहें और समान एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए एक साथ आगे बढ़ते रहें। विश्व कल्याण का यह विचार आज तक किसी अन्य देश के राष्ट्र प्रमुख ने नहीं दिया। क्योंकि ये देश असमानता के संदर्भ में ही अपने पूंजीवादी, बाजारवादी और उपभोक्तावादी एजेंडे को आगे बढ़ाते रहे हैं। पश्चिमी देशों द्वारा हथियारों का उत्पादन और फिर उनके खपाने का प्रबंध कई देशों की प्रत्यक्ष लड़ाई और देशों के भीतर ही धर्म और संस्कृति के अंतर्कलह देखने में आते रहे हैं। अतएव विश्वव्यापी भाईचारे के लिए वसुधैव कुटुंबकम् से उतम कोई दूसरा विचार हो ही नहीं सकता।

जी20 शिखर सम्मेलन में प्रधान मंत्री का प्रारंभिक वक्तव्य - Excellencies, नमस्कार!

औपचारिक कार्यवाही शुरू करने से पहले, हम सभी की ओर से कुछ देर पहले मोरक्को में आये भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करना चाहता हूँ।

हम प्रार्थना करते हैं की सभी इन्जुरड लोग शीघ्र स्वस्थ हों। इस कठिन समय में पूरा विश्व समुदाय मोरक्को के साथ हैं और हम उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए तैयार हैं।

G-20 के प्रेसिडेंट के तौर पर, भारत, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। इस समय जिस स्थान पर हम एकत्रित हैं, यहाँ से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर लगभग ढाई हजार साल पुराना एक स्तंभ लगा हुआ है। इस स्तंभ पर प्राकृत भाषा में लिखा है-

"हेवम लोकसा हितमुखे तित्, अथ इयम नातिसु हेवम"

अर्थात्, मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए।

ढाई हजार साल पहले, भारत की भूमि ने, यह संदेश पूरे विश्व को दिया था।

आइए, इस सन्देश को याद कर, इस G-20 समिट का हम आरम्भ करें। इक्कीसवीं सदी का यह समय, पूरी दुनिया को नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है, जब बरसों पुरानी चुनौतियाँ, हमसे नए समाधान मांग रही हैं।

और इसलिए, हमें Human Centric अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने, इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं, तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं।

आज G-20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है, कि हम मिलकर सबसे पहले इस Global Trust Deficit को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है।

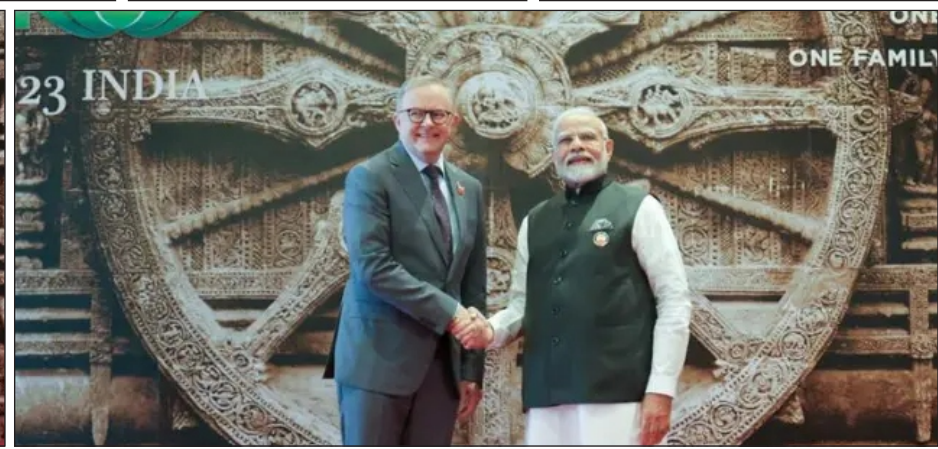
और इसलिए, "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल हो,

नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो,

ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, Food, Fuel और Fertiliser का मैनेजमेंट हो, Terrorism और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वॉटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही, आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने कोणार्क चक्र के सामने किया विश्व नेताओं का स्वागत, देखिए तस्वीरें



भारत में इतिहास का सबसे सफल जी-20 सम्मेलन, भारत का कद बढ़ा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने जी-20 का सफल आयोजन करके इतिहास रच दिया। दिल्ली घोषणापत्र पर सर्वसम्मति ऐतिहासिक रही, जिसे ज्यादातर लोग असंभव बता रहे थे। दिल्ली के राजघाट पर दुनिया के सबसे विकसित देशों के राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष और बड़े नेताओं ने जिस तरह एक साथ अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी को नमन किया, यह दृश्य देखकर हर भारतीय गर्व से भर गया और सबके मन में एक ही ख्याल आया कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए और यह काबिलियत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ही है। पीएम मोदी के नेतृत्व कौशल और कूटनीति पर मुहर लगाते हुए सम्मेलन में शामिल वैश्विक नेताओं ने एक स्वर में माना कि भारत ने जिस तरह की नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया है वह अद्भुत है। जी-20 की अगली अध्यक्षता संभालने वाले ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्व्वा ने स्वीकार किया कि भारतीय नेतृत्व ने जो लकीर खींच दी है उनके लिए उस तक पहुंचना बहुत बड़ी चुनौती होगी। यहां तक कि भारत के विरुद्ध बोलने वाले तुर्किये के राष्ट्रपति तैयप एर्दोगन भी यह सब देखकर अचंभित थे और पीएम मोदी की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए।



भारत की अध्यक्षता में आयोजित जी-20 के शिखर सम्मलेन में स्वच्छ ऊर्जा के मामले में भारत की ओर से एक और महत्वपूर्ण पहल का ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च करने की घोषणा की। उन्होंने नए अलायंस की शुरुआत करते हुए दुनिया के देशों से उससे जुड़ने का आह्वान किया। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस दुनिया में वैकल्पिक व स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने का प्रयास है। भारत के अलावा अमेरिका और ब्राजील इस नए अलायंस के संस्थापक सदस्य हैं। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के लॉन्च होने के बाद तीनों संस्थापक सदस्य समेत अर्जेंटीना और इटली जैसे कुल 11 देश इससे जुड़ चुके हैं। सदस्य देशों के कई नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की पहल की सराहना की। वहीं जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने 'मिशन लाइफ' की अवधारणा के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की।

जी-20 सम्मेलन पर भारतीयता की छाप छोड़ने में सफल रही मोदी सरकार प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम ने जी-20 सम्मेलन को पूरी तरह से भारतीय संस्कृति के रंग में रंग दिया। जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत की समृद्ध संस्कृतिक विरासत

वैश्विक आयोजन के केंद्र में रहीं। इनमें कोणार्क मंदिर, नालंदा विश्वविद्यालय, नटराज की मूर्ति, ऋग्वेद की पांडुलिपियां, भीमबेटका के गुफा की तस्वीरें आदि प्रमुख हैं। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में हिस्सा लेने आए राष्ट्राध्यक्षों व मेहमानों का स्वागत करने के लिए जो स्थान चुना था, इसके पीछे कोणार्क के ऐतिहासिक सूर्य मंदिर के चक्र की प्रतिकृति लगी थी। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को प्रतिकृति से परिचित भी कराया। वहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार रात भारत मंडपम स्थल पर विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों और विश्व के अन्य नेताओं का स्वागत किया। इस दौरान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल बिहार का प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा था। ऋषि सुनक सहित कुछ नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी विश्वविद्यालय के महत्व के बारे में बताते नजर आए। भारत मंडपम के सांस्कृतिक गलियारे में पाणिनी का व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी, ऋग्वेद की पांडुलिपियां, सूर्य द्वार नामक मूर्तिकला और मध्य प्रदेश के भीमबेटका गुफा चित्रों की डिजिटल तस्वीरें प्रदर्शित की गईं।

8 देशों का इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन को जवाब देगा

दिल्ली में G20 समिट ने दुनिया में भारत की भागीदारी के कई दरवाजे खोले हैं। समिट में इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई। भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय यूनियन सहित कुल 8 देशों के इस प्रोजेक्ट का फायदा इजरायल और जॉर्डन को भी मिलेगा। मुंबई से शुरू होने वाला यह नया कॉरिडोर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) का विकल्प होगा। यह कॉरिडोर 6 हजार किमी लंबा होगा। इसमें 3500 किमी समुद्र मार्ग शामिल है। कॉरिडोर के बनने के बाद भारत से यूरोप तक सामान पहुंचाने में करीब 40 प्रतिशत समय की बचत होगी। अभी भारत से किसी भी कार्गो को शिपिंग से जर्मनी पहुंचने में 36 दिन लगते हैं, इस रूट से 14 दिन की बचत होगी। यूरोप तक सीधी पहुंच से भारत के लिए आयात-निर्यात आसान और सस्ता होगा।

भारत ने संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका के साथ मिलकर महाद्वीपों में आर्थिक एकीकरण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप इकोनॉमिक गलियारे के लॉन्च का ऐलान किया।

आधिकारिक तौर पर इसे इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का नाम दिया गया है। इसके साथ ही इसे आधुनिक स्पाइक रूट के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। यह गलियारा इतना अहम इसलिए है क्योंकि इसके निर्माण के साथ ही दुनिया के 'व्यापार का भूगोल' बदल जाएगा। इस स्टोरी में जानते हैं कि भारतयूरोप तक आर्थिक गलियारा बनाकर चीन के सपनों और पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी कैसे फेरेगा?



मानव-केंद्रित वैश्वीकरण: हमें जी20 को दुनिया के अंतिम छोर तक ले जाना है, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है- पीएम

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जी-20 की मेजबानी और वैश्विक मुद्दों को लेकर एक OpEd लिखा है। आप भी पढ़िए प्रधानमंत्री मोदी का OpEd- 'वसुधैव कुटुम्बकम्' – हमारी भारतीय संस्कृति के इन दो शब्दों में एक गहरा दार्शनिक विचार समाहित है। इसका अर्थ है, 'पूरी दुनिया एक परिवार है'। यह एक ऐसा सर्वव्यापी दृष्टिकोण है जो हमें एक सार्वभौमिक परिवार के रूप में प्रगति करने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक ऐसा परिवार जिसमें सीमा, भाषा और विचारधारा का कोई बंधन ना हो।

जी-20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान, यह विचार मानव-केंद्रित प्रगति के आह्वान के रूप में प्रकट हुआ है। हम One Earth के रूप में, मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक साथ आ रहे हैं। हम One Family के रूप में विकास के लिए एक-दूसरे के सहयोगी बन रहे हैं। और One Future के लिए हम एक साझा उज्ज्वल भविष्य की ओर एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना वैश्विक महामारी के बाद की विश्व व्यवस्था इससे पहले की दुनिया से बहुत अलग है। कई अन्य बातों के अलावा, तीन महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। पहला, इस बात का एहसास बढ़ रहा है कि दुनिया के जीडीपी-केंद्रित दृष्टिकोण से हटकर मानव-केंद्रित दृष्टिकोण की ओर बढ़ने की आवश्यकता है।

दूसरा, दुनिया ग्लोबल सप्लाइ चेन में सुदृढ़ता और विश्वसनीयता के महत्व को पहचान रही है।

तीसरा, वैश्विक संस्थानों में सुधार के माध्यम से बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने का सामूहिक आह्वान सामने है।

जी-20 की हमारी अध्यक्षता ने इन बदलावों में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है।

दिसंबर 2022 में जब हमने इंडोनेशिया से अध्यक्षता का भार संभाला था, तब मैंने यह लिखा था कि जी-20 को मानसिकता में आमूल-चूल परिवर्तन का वाहक बनना चाहिए।

विकासशील देशों, ग्लोबल साउथ के देशों और अफ्रीकी देशों की हाशिए पर पड़ी आकांक्षाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए इसकी विशेष आवश्यकता है।

इसी सोच के साथ भारत ने 'वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट' का भी आयोजन किया था। इस समिट में 125 देश भागीदार बने। यह भारत की अध्यक्षता के तहत की गई सबसे महत्वपूर्ण पहलों में से एक रही। यह ग्लोबल साउथ के देशों से उनके विचार, उनके अनुभव जानने का एक महत्वपूर्ण प्रयास था। इसके अलावा, हमारी अध्यक्षता के तहत न केवल अफ्रीकी देशों की अबतक की सबसे बड़ी भागीदारी देखी गई है, बल्कि जी-20 के एक स्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने पर भी जोर दिया गया है।

हमारी दुनिया परस्पर जुड़ी हुई है, इसका मतलब यह है कि विभिन्न क्षेत्रों में हमारी चुनौतियां भी आपस में जुड़ी हुई हैं। यह 2030 एजेंडा के मध्य काल का वर्ष है और कई लोग चिंता जता रहे हैं कि सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के मुद्दे पर प्रगति पटरी से उतर गई है।

एसडीजी के मोर्चे पर तेजी लाने से संबंधित जी-20 2023 का एक्शन प्लान भविष्य की दिशा निर्धारित करेगा। इससे एसडीजी को हासिल करने का रास्ता तैयार होगा।

भारत में, प्राचीन काल से प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर आगे बढ़ना



हमारा एक आदर्श रहा है और हम आधुनिक समय में भी क्लाइमेट एक्शन में अपना योगदान दे रहे हैं।

ग्लोबल साउथ के कई देश विकास के विभिन्न चरणों में हैं और इस दौरान क्लाइमेट एक्शन का ध्यान रखा जाना चाहिए। क्लाइमेट एक्शन की आकांक्षा के साथ हमें ये भी देखना होगा कि क्लाइमेट फाइनेंस और ट्रांसफर ऑफ टेक्नॉलजी का भी ख्याल रखा जाए।

हमारा मानना है कि जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए पाबंदियों वाले रवैये को बदलना चाहिए। 'क्या नहीं किया जाना चाहिए' से हटकर 'क्या किया जा सकता है' वाली सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। हमें एक रचनात्मक कार्यसंस्कृति पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

एक टिकाऊ और सुदृढ़ ब्लू इकॉनमी के लिए चेन्नई एचएलपी हमारे महासागरों को स्वस्थ रखने में जुटी है। ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन सेंटर के साथ, हमारी अध्यक्षता में स्वच्छ एवं ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित एक ग्लोबल इकोसिस्टम तैयार होगा।

वर्ष 2015 में, हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का शुभारंभ किया था। अब, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के माध्यम से हम दुनिया को एनर्जी ट्रांजिशन के योग्य बनाने में सहयोग करेंगे। इससे सर्कुलर इकॉनमी का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा।

क्लाइमेट एक्शन को लोकतांत्रिक स्वरूप देना, इस आंदोलन को गति प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका है। जिस प्रकार लोग अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर रोजमर्रा के निर्णय लेते हैं, उसी प्रकार वे इस धरती की सेहत पर होने वाले असर को ध्यान में रखकर अपनी जीवनशैली तय कर सकते हैं। जैसे योग वैश्विक जन आंदोलन बन गया है, उसी तरह हम 'लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबल इनवायरमेंट' (LiFE) को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं।

जलवायु परिवर्तन के कारण, खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती होगी। इससे निपटने में मोटा अनाज या श्रीअन्न से बड़ी मदद मिल सकती है। श्रीअन्न क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा दे रहा है। इंटरनेशनल इयर ऑफ मिलेट्स के दौरान हमने श्रीअन्न को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया है। द डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल्स ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन से भी इस दिशा में सहायता मिल सकती है।

टेक्नॉलजी परिवर्तनकारी है लेकिन इसे समावेशी भी बनाने की जरूरत है। अतीत में, तकनीकी प्रगति का लाभ समाज के सभी वर्गों को समान रूप से नहीं मिला। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने दिखाया है कि कैसे टेक्नॉलजी का लाभ उठाकर असमानताओं को कम किया जा सकता है।



90 हजार गांवों में संपत्ति कार्ड तैयार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को समृद्धि की राह पर ले जाने और विकसित भारत बनाने के लिए हर मोर्चे पर काम कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों से कस्बे तक में देश में संपत्ति विवाद एक बड़ी समस्या रही है। ग्रामीण इलाकों में कई पीढ़ियों तक चलने वाले संपत्ति विवाद की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए पीएम मोदी ने अपने दूरदर्शी विजन से प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत 24 अप्रैल, 2020 की। इसके तहत गांव के उन लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिया जा रहा है, जिनकी जमीन किसी भी सरकारी आंकड़े में दर्ज नहीं है। इस योजना को देशभर में अमलीजामा पहनाने के लिए मोदी सरकार पूरे देश में ग्रामीण इलाकों का सेटेलाइट सर्वे कराकर संपत्ति के रिकॉर्ड को डिजिटल बना रही है। देश के करीब 90 हजार गांवों में संपत्ति कार्ड बनकर तैयार हो चुके हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को समृद्धि की राह पर ले जाने और विकसित भारत बनाने के लिए हर मोर्चे पर काम कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों से कस्बे तक में देश में संपत्ति विवाद एक बड़ी समस्या रही है। ग्रामीण इलाकों में कई पीढ़ियों तक चलने वाले संपत्ति विवाद की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए पीएम मोदी ने अपने दूरदर्शी विजन से प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत 24 अप्रैल, 2020 को की। इसके तहत गांव के उन लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिया जा रहा है, जिनकी जमीन किसी भी सरकारी आंकड़े में

दर्ज नहीं है। इस योजना को देशभर में अमलीजामा पहनाने के लिए मोदी सरकार पूरे देश में ग्रामीण इलाकों का सेटेलाइट सर्वे कराकर संपत्ति के रिकॉर्ड को डिजिटल बना रही है। देश के करीब 90 हजार गांवों में संपत्ति कार्ड बनकर तैयार हो चुके हैं।

अब तक देश के 89,749 गांवों में संपत्ति कार्ड तैयार देशभर में 26 जुलाई, 2023 तक 89,749 गांवों में संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा स्वामित्व योजना के तहत तैयार किए गए

आवास नहीं मिला तो अब छोड़े चिंता, MP सरकार शुरू कर रही नई योजना



प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आवासहीनों के लिए सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री जन आवास योजना लागू करेगी। इसमें भूखंड देने के अलावा हाइराइज बिल्डिंग बनाकर आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए वे गरीब व्यक्ति पात्र होंगे, जिनके नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं जुड़ पाए हैं। यह जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कलेक्टर-कमिश्नर, आइजी-एसपी कांफ्रेंस में दी। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि त्योहारों का समय है, कानून व्यवस्था चाकचौबंद रखें। सावधानी में कोई कमी न आए।

प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आवासहीनों के लिए सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री जन आवास योजना लागू करेगी। इसमें भूखंड देने के अलावा हाइराइज बिल्डिंग बनाकर आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए वे गरीब व्यक्ति पात्र होंगे, जिनके नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं जुड़ पाए हैं। यह जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कलेक्टर-कमिश्नर, आइजी-एसपी कांफ्रेंस में दी। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि त्योहारों का समय है, कानून व्यवस्था चाकचौबंद रखें। सावधानी में कोई कमी न आए।

मुख्यमंत्री आवास स्थित कार्यालय से सीएम ने वर्चुअली अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि जितने भी गरीब प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित हैं, उनके लिए हम जल्द ही योजना लागू करने वाले हैं। जिनमें ऐसे व्यक्तियों की सूची बनेगी। आप सभी ध्यान दें कि सूची बनाने में कोई अनैतिक कार्य न शुरू हो जाए। इस बार ग्वालियर से दस सितंबर को लाइली बहनों के खातों में पैसे डालूंगा। कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शांति समिति की बैठक कर आवश्यक निर्णय लें। शांति सुरक्षा का माहौल बनाएं। सावधानी में कोई कमी न आए। उन्होंने पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना को निर्देश दिए कि आप भी



समीक्षा करते रहें ताकि त्योहार के समय कानून व्यवस्था बेहतर रहे।

सोयाबीन की फसलों को नुकसान हुआ है, हम भरपाई करेंगे

मुख्यमंत्री ने फसलों की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि अभी वर्षा हो रही है, जो प्रसन्नता की बात है पर कुछ जगहों पर सोयाबीन की फसल को नुकसान हुआ है। किसान चिंता न करें। किसान कल्याण मेरी सरकार का मिशन है। जहां भी अल्प वर्षा के कारण नुकसान हुआ, वहां राहत और फसल बीमा का पैसा देंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वास्तविकता के आधार पर आकलन कर क्षतिपूर्ति देने का काम करें।

बिजली स्थिति अब सामान्य है पर अभी एक बार और समीक्षा की जाएगी। ऊर्जा विभाग के साथ-साथ कलेक्टर-कमिश्नर भी आपूर्ति की स्थिति देखें। कृषि कार्य के लिए 10 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित कराएं। जिले की जल उपयोगिता समिति की बैठक जरूर करा लें। बांध में पानी है तो बैठक कर तय करें कि पानी की आपूर्ति सुनिश्चित हो जाए। कलेक्टर-कमिश्नर रबी की फसल की बोवनी के पहले पूरा आकलन कर विभाग को बताएं। खाद्यान्न की आपूर्ति में कहीं कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। यदि कहीं कोई कमी है ताकि समय पर व्यवस्था हो जाए।

जीवनस्तर सुधार कर अपनी किस्मत खुद बदल रही हैं स्व सहायता समूह की महिलायें



यह एक महिला समूह की उनकी मेहनत और संघर्ष की कहानी है। महासमुंद विकासखंड के ग्रामीण अंचल की महिलाएं स्वसहायता समूह से जुड़कर सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान की मिसाल कायम कर रही हैं। बिहान योजना से जुड़ी महिलायें विभिन्न आजीविका को अपने रोजगार का साधन बना रही हैं। ग्राम पंचायत शेर की सुआ महिला स्वसहायता समूह की महिलायें तार जाली का निर्माण कर खेत-खलिहानों व बागड़ काम में आने वाली विभिन्न प्रकार की लोहे के तार की जाली का निर्माण कर रही। बिहान योजना से जुड़ी महिलायें विभिन्न आजीविका को अपने रोजगार का साधन बना रही हैं।

इस समूह के द्वारा अब तक 2000 बंडल तार जाली का निर्माण कर लिया गया है, जिसको सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में विक्रय कर लगभग 6 लाख रूपए की आय प्राप्त कर चुकी है। समूह की अध्यक्ष श्रीमती दिव्या नायक बताती है कि समूह में जुड़ने से

पहले किसी दूसरे के यहां तार जाली बनाने का कार्य करने जाती थी। तक्ररीबन दो साल पहले बिहान अंतर्गत समूह से जुड़ने हेतु प्रेरित किया गया और समूह से जुड़ कर महिलाएं कैसे आत्मनिर्भर बन सकती हैं कैसे खुद का स्वयं व्यवसाय कर सकती हैं इन सबकी जानकारी मिली। हम सब 11 महिलाएं मिलकर, सुआ महिला स्वसहायता समूह का गठन किया। गठन उपरांत समूह को आरएफ की राशि 15000 रूपये अनुदान के रूप में प्रदाय किया गया साथ ही 2 लाख का ऋण भी समूह को प्रदाय किया गया। अन्य के यहां से तारजाली कार्य सीखने के बाद स्वयं का तार जाली बनाने का काम शुरू किया। प्राप्त ऋण से मशीन और संबंधित सामग्री खरीदी और उत्पादन करना शुरू किया। बिहान योजना से मिले सहयोग की वजह से आज हम सब बहने आत्मनिर्भर बने हैं।

गौरतलब है कि स्व सहायता समूह की महिलाएं

अक्सर सामुदायिक आर्थिक विकास के लिए साथ मिलकर काम करती हैं। समूह के माध्यम से महिलाएं संयुक्त रूप से धन जुटा सकती हैं, लोन ले सकती हैं, और व्यापारिक क्रियाओं में शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा, इन समूहों में महिलाएं आपस में ज्ञान और अनुभव साझा कर सकती हैं, जिससे उनका विकास होता है और उन्हें सामाजिक समरसता की दिशा में भी मदद मिलती है। ये महिलाएं विभिन्न काम करके अपने परिवारों को पालने और अपने जीवनस्तर में सुधार करने का संघर्ष कर अपनी किस्मत बदल रही हैं और समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इस तरह के महिला समूहों की साहस, संघर्ष, और सफलता को प्रकट करती हैं, और अन्य महिलाओं को समृद्धि की ओर बढ़ने में मदद करती हैं। इन समूहों में महिलाएं साथियों के साथ आर्थिक संगठन और विकास के लिए आगे आ रही हैं।

गांव के हर घर में पोषण बाड़ी



मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की परिकल्पना साकार होने लगी है। जिला बीजापुर अंतर्गत एकीकृत महिला बाल विकास परियोजना बीजापुर सेक्टर के नयापारा नैमेड़ गांव के हर घर में पोषण बाड़ी बनाई तो केंद्र के सभी बच्चे कुपोषण से बाहर हुए। गांव के आंगनबाड़ी केंद्र में हरी साग सब्जियां लगाकर पोषण बाड़ी तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुपोषण को दूर करने के लिए हर घर में पोषण बाड़ी बनाने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। इसका साकारात्क परिणाम भी देखने को मिल रहा है।

छत्तीसगढ़ सरकार के उद्यानिकी विभाग की पोषण बाड़ी योजना से कई परिवारों की बाड़ी लहलहा रही है। इससे उनके दैनिक जरूरत के लिए सब्जी आसानी से मिल जाती है। सब्जी बेचकर घर की कुछ जरूरतें भी पूरी हो जा रही है, विलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत बेलपान के संतोष मरावी और सुहागदास मानिकपुरी अपनी बाड़ी में उद्यानिकी विभाग की मदद से सब्जी लगा रहे हैं।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती ज्योति पटेल द्वारा पोषण बाड़ी की हरी साग सब्जी को गर्म भोजन बच्चों और महिलाओं को खिला रही है। ज्योति पटेल अपने सेक्टर सुपरवाइजर के साथ प्रत्येक हितग्राहियों के घर गृहभेंट करके पोषण बाड़ी बनाने और खान पान में हरी साग सब्जियों को शामिल करने प्रेरित भी करती है।

आज बीजापुर के दूरस्थ अंचल गांव नैमेड़ नयापारा में प्रत्येक हितग्राही के घर में पोषण बाड़ी बनी हुई है। और नियमित अपने भोजन में हरी साग-सब्जियों का सेवन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत मिलने वाले अंडा, मिलेट, चिक्की और दलिया का भी उपयोग कर रहे हैं। वर्तमान में एक भी कुपोषित बच्चे नहीं हैं। गांव को कुपोषण से मुक्त करने में आंगनबाड़ी सहायिका रामदुलारी का विशेष सहयोग रहता है।

अपने दिनचर्या में प्रतिदिन संतुलित आहार का सेवन करने से दिनभर शरीर और मन में ताजगी बनी रहती है। संतुलित आहार आपकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। भोजन में हरी साग-सब्जियां, फल-फूल, दूध-दही को शामिल करना चाहिए इसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा खनिज आदि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से बच्चों और महिलाओं को पौष्टिक आहार मिले इसके लिए घर घर में पोषण बाड़ी तैयार करवाई जा रही है। इसका लाभ परिवार के सभी सदस्यों को मिल रहा है।

सब्जियां लगाई हैं

संतोष मरावी ने बताया कि अपनी बाड़ी में उन्होंने भुट्टा, सेमी, भिन्डी और लौकी लगाई है। उद्यानिकी विभाग की पोषण बाड़ी योजना के अंतर्गत उन्हें विभिन्न प्रकार की सब्जी किट निःशुल्क प्रदाय की गयी है। इसी प्रकार श्री सुहागदास मानिकपुरी ने अपनी बाड़ी में भिन्डी, तोरई, लौकी और लाल बाड़ी उद्यानिकी विभाग द्वारा प्रदान की गयी सहायता से लगायी है।

परिवार का खर्च निकल जाता है

इन सब्जियों से उनके घर में उपयोग के लिए सब्जी की दैनिक जरूरत तो पूरी हो ही जाती है। इसके अलावा ज्यादा उत्पादन होने पर वे दैनिक सब्जियों को साप्ताहिक बाजार में बेच भी देते हैं जिससे परिवार का कुछ खर्च भी निकल जाता है।

इसी प्रकार सुहागदास मानिकपुरी बाड़ी में भिन्डी, तोरई, लौकी और लाल बाड़ी विभाग द्वारा प्रदान की गई सहायता लगाई गई है। इन सब्जियों से उनके घर में उपयोग के लिए सब्जी की दैनिक जरूरत तो पूरी ही हो जाती है। इसके अलावा ज्यादा उत्पादन होने पर वे सब्जियों को साप्ताहिक बाजार में भी बेच देते हैं। जिससे परिवार का खर्च भी निकल जात है।



जी20 लीडर्स के घोषणापत्र में कही गई 10 अहम बातें

नई दिल्ली जी20 लीडर्स के इस घोषणापत्र में जी20 समूह ने कहा कि मजबूत, दीर्घकालिक, संतुलित और समावेशी विकास में तेजी लाने के लिए काम किया जाएगा। इसके साथ ही सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडे को लागू करने की दिशा में काम होगा।

इसमें रूस के विदेश मंत्री की मौजूदगी के बावजूद यूक्रेन युद्ध का जिक्र है। रूस और उसके समर्थक देशों की मौजूदगी में यूक्रेन युद्ध की निंदा की गई। पश्चिमी देशों और रूस के बीच भारत ने मध्यस्थता की जो कोई नहीं कर पाया।

घोषणापत्र में कहा गया कि हम शांति के लिए सभी धर्मों की प्रतिबद्धता को स्वीकार करते हैं और नस्लवाद और असहिष्णुता के अन्य रूपों समेत आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा करते हैं।

नई दिल्ली जी20 लीडर्स घोषणा पत्र में कहा गया कि हम सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी पीछे न छूटे। हम 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए भारतीय राष्ट्रपति पद के प्रयासों की सराहना करते हैं।

जी20 ने अपने संयुक्त घोषणापत्र में कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव ए/आरईएस/77/318, विशेष रूप से धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता, संवाद और सहिष्णुता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता के प्रति संकल्पित हैं।

इस घोषणापत्र में आगे कहा गया कि हम महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को प्रोत्साहित करते हैं और वैश्विक चुनौतियों से निपटने और समाज के सभी क्षेत्रों के रूप में योगदान देने के लिए निर्णय निर्माताओं के रूप में महिलाओं की पूर्ण, समान, प्रभावी और सार्थक भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

घोषणापत्र में कहा गया कि हम भारत की जी-20 अध्यक्षता के दौरान स्टार्ट-अप 20 एंजेलमेंट ग्रुप की स्थापना और इसके जारी रहने का स्वागत करते हैं।

हम घोषणापत्र में शामिल डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के माध्यम से वित्तीय समावेशन और उत्पादकता लाभ को आगे बढ़ाने के लिए स्वैच्छिक और गैर-बाध्यकारी जी-20 नीति सिफारिशों का समर्थन करते हैं।

इसके साथ ही नई दिल्ली घोषणापत्र में निजी व्यवसाय को लेकर कहा गया कि हम सतत विकास को गति देने और आर्थिक परिवर्तन को आगे बढ़ाने में निजी उद्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हैं।

घोषणापत्र में कहा गया कि हम विकसित देशों से अपनी संबंधित ओडीए प्रतिबद्धताओं को पूरी तरह से पूरा करने का आह्वान करते हैं।

यूपी में इन्वेस्टर्स को हर सुविधा की गारंटी

- पूरे देश में विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सकारात्मक माहौल : सीएम योगी
- उत्तर प्रदेश में बेहिचक निवेश करें, सरकार साथ खड़ी मिलेगी : योगी
- 97 उद्यमियों को 102 भूखंडों का आवंटन, 14 को सीएम ने दिए आवंटन सह आशय पत्र

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने वालों तथा उद्योग लगाने वालों को सरकार की तरफ से आश्चस्त करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में निवेशकों व उद्यमियों को सुरक्षा और हर तरह की सुविधा की पूरी गारंटी है। निवेशकों, उद्यमियों के सामने किसी तरह की समस्या सामने नहीं आने दी जाएगी, न तो सुरक्षा के मामले में और न ही शासन की किसी सुविधा के मामले में। वे बेहिचक उत्तर प्रदेश में निवेश करें, सरकार उनके साथ खड़ी मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 102 उद्योगों के लिए जमीन का आवंटन हो चुका है। उद्योग लगने लगेंगे तो लोगों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू होगी। इसके दृष्टिगत उन्होंने एक बार फिर गीडा प्रशासन से कहा कि वह स्थानीय नौजवानों के स्किल डेवलपमेंट के लिए केंद्र खोलकर स्थानीय उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार कोर्स चलाए।

ताकि अधिक से अधिक स्थानीय युवाओं का यहां के उद्योगों में समायोजन हो सके। यहीं नौकरी मिलने पर नौजवानों को कोरोना जैसी आपदा में पलायन का दंश नहीं झेलना पड़ेगा और वे घर गृहस्थी का पालन करते हुए उद्योग को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे पाएंगे।



सीएम योगी गीडा के सेक्टर 26 में 110 करोड़ रुपये के निवेश वाली तत्वा प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री का उद्घाटन, 136 करोड़ रुपये के अवस्थापना कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण और 97 उद्यमियों को 102 भूखंडों के आवंटन सह आशय पत्र वितरण के लिए आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने निवेशकों और उद्यमियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि सुरक्षा का माहौल देने के साथ ही सरकार हर तरह की सुविधा का लाभ दे रही है। निवेश मित्र और निवेश सारथी जैसे ऑनलाइन पोर्टल इसके लिए बनाए गए हैं। बिना किसी बाधा के निवेशकों को सरकार की तरफ से इंसेंटिव प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश के अंदर एक सकारात्मक माहौल बना है। यह माहौल विकास, सुरक्षा व समृद्धि का है। जब प्रत्येक व्यक्ति के एजेंडे में विकास होता है तो वह हर तरीके से उसके लिए माहौल बनाने में अपना योगदान देता है।

असुरक्षित वातावरण में नहीं होता निवेश, अवमूल्यन की ओर जाती हैं संस्थाएं - सीएम योगी ने कहा कि सभी लोग जानते हैं कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी। और, उसमें भी आज से पांच-सात साल पहले गोरखपुर की स्थिति क्या हुआ करती थी। अपराधी और माफिया हर एक व्यवस्था पर हावी था। अराजकता चरम पर थी। प्रदेश में हर दूसरे-तीसरे दिन एक दंगा होता था। भ्रष्टाचार चरम पर था। इस माहौल में राज्य के युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था। विकास कार्य ठप हो गए थे। असुरक्षित वातावरण में कोई निवेश नहीं करता। सभी संस्थाएं अवमूल्यन की ओर जाती हैं। यही स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही थी। पर, पिछले छह वर्ष के अंदर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आने के बाद

प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र जी के मार्गदर्शन व नेतृत्व में आज सभी लोगों ने बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा है।

स्लाटर हाउस नहीं, एथेनाल प्लांट, डेरी व पाइप फैक्ट्री बन रही इस क्षेत्र की पहचान - मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गीडा का यह वही क्षेत्र है जहां पर 2005-06 में समाजवाद पार्टी की सरकार में स्लाटर हाउस लगाने का कार्य हो रहा था। आज यहां स्लाटर हाउस नहीं बल्कि एथेनाल का प्लांट लगाता है। हर घर नल की योजना के लिए पाइप की फैक्ट्री लगती है। डेरी का प्लांट लगाता है। इन सबसे हजारों नौजवानों को रोजगार मिलता है। मुख्यमंत्री ने तत्वा प्लास्टिक के कर्मचारियों से अपनी बातचीत का स्मरण साझा करते हुए कहा कि यहां अधिकांश कामगार पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों से ही हैं। यदि पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवान को अपने घर के पास जनपद या क्षेत्र में ही रोजगार मिल जाएगा तो उसे अपना घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। ऐसे ही रोजगार का दृश्य आज हमें गीडा में देखने को मिल रहा है।

यूपी को मिले हैं 36 लाख करोड़ रुपये के प्रस्ताव - मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 से 12 फरवरी 2023 के बीच उत्तर प्रदेश के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हुआ था। इसमें उत्तर प्रदेश को 36 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। अकेले गोरखपुर को करीब पौने दो लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले। 36 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों के धरातल पर उतरने पर एक करोड़ नौजवानों को नौकरी व रोजगार मिलने की संभावना है। गीडा में 102 नए उद्योगों की स्थापना के लिए आशय पत्र के वितरण का कार्य इसी संभावना को आगे बढ़ाएगा।

जिम्मेदार खनन विकास में सुस्थिरता ला निरंतर मजबूती की ओ

एनएमडीसी लिमिटेड की 65वीं वार्षिक

एनएमडीसी लौह और इस्पात क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क की उपलब्धता सुनिश्चित करके, हम भारत की औद्योगिक प्रगति में महत्वपूर्ण सहायक हैं। इस्पात उद्योग के साथ हमारी साझेदारी राष्ट्र की विकास यात्रा की आधारशिला है और हमें इस जिम्मेदारी पर बहुत गर्व है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने 408 लाख टन का उत्पादन और 382 लाख टन की बिक्री दर्ज की है, परिचालन से 17,667 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। कर-पूर्व लाभ (पीबीटी) 7,637 करोड़ और कर-पश्चात लाभ (पीएटी) 5,529 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी का नेटवर्थ 22,332 करोड़ रुपये रहा जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 25% अधिक है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 3.75 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश और 2.85 रुपये प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की घोषणा की, जिससे संचयी लाभांश 6.60 रुपये प्रति शेयर हो गया।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की डीमर्जर योजना के तहत एनएमडीसी स्टील लिमिटेड (एनएसएल) को एनएमडीसी लिमिटेड से एक अलग कंपनी में डिमर्जर कर दिया गया, जिसका आदेश 6 अक्टूबर 2022 को पारित किया गया था। डिमर्जर के बाद, एनएसएल के शेयरों को 20 फरवरी 2023 को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया गया। एनएसएल के पास एनएमडीसी लिमिटेड की मिरर शेयरहोल्डिंग के रूप में 60.79% की भारत सरकार की शेयरधारिता और वर्तमान में 39.21% की सार्वजनिक शेयरधारिता है। एनएमडीसी स्टील लिमिटेड का डीमर्जर अक्टूबर 2022 में सफलतापूर्वक पूरा हो गया था। विस्तार, मूल्य वर्धन और अग्रगामी एकीकरण के भाग के रूप में और भारत सरकार तथा छत्तीसगढ़ सरकार की इच्छा के अनुरूप, एनएमडीसी स्टील लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ में 3 एमटीपीए क्षमता के ग्रीनफील्ड एकीकृत इस्पात संयंत्र का संचालन प्रारम्भ कर दिया है।

एनएमडीसी ने ग्राहकों को निर्बाध आपूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ के कुमार मारेंगा में एक मध्यवर्ती लौह अयस्क स्टॉकयार्ड भी विकसित किया है। यह स्टॉकयार्ड चालू वित्त वर्ष में प्रारम्भ हो गया है और हमारे उत्पादन और निकासी क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक मूल्यवान कदम साबित हो रहा है।

इन घटनाक्रमों के आधार पर हम वित्त वर्ष 2024 में 470 से 490 लाख टन लौह अयस्क के उत्पादन का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। यह मात्रा वित्त वर्ष 2023 में हमारे उत्पादन की तुलना में 20% अधिक है और हमें उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2024 में भी हम पुनः सर्वोच्च स्तर को पार कर जाएंगे।

हमने वित्त वर्ष 2024 में मजबूत गति के साथ प्रवेश किया है। वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में संचयी उत्पादन में 20% और बिक्री में 41% की वृद्धि हुई, जो कंपनी के इतिहास में पहली तिमाही का सबसे अच्छा उत्पादन और बिक्री है। एनएमडीसी ने इस वित्तीय वर्ष में अब तक के 5 में से 4 सर्वश्रेष्ठ मासिक निष्पादन दर्ज किए हैं। वित्त वर्ष 2024 के हर महीने में कंपनी की दुलाई लगातार उत्पादन से अधिक रही है।

वॉल्यूम में यह निरंतर वृद्धि निवेश का परिणाम है, जो कि कंपनी की महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप है। आपकी कंपनी ने अगस्त 2023 तक पूंजीगत व्यय लक्ष्य का दोगुना पहले ही प्राप्त कर लिया है और पिछले वर्ष की इस अवधि के वास्तविक आंकड़ों की तुलना में 60% अधिक कैपेक्स को प्राप्त किया है।

हमारे भविष्य की योजनाओं में बचेली सेक्टर में प्रॉडक्ट मिक्स की गुणवत्ता में सुधार, बचेली में नई स्कीनिंग लाइन की शुरुआत और किरंदुल में 'टैपिड वेगन लोडिंग सिस्टम' के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

अपशिष्ट खनन और निकासी क्षमता में वृद्धि खदानों के जीवन को बढ़ाने के लिए प्रमुख क्षेत्र हैं इसलिए बचेली में 'बेनिफिकेशन प्लांट' का निर्माण और बचेली से नगरनार तक 'स्लरी पाइपलाइन' बिछाने की परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। हम 'स्लरी पाइपलाइन' और इससे सम्बद्ध 'बेनिफिकेशन प्लांट' और 'पैलेट प्लांट' चरणों में स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं, जिससे कि लौह अयस्क की किफायती दुलाई ऐसे स्थानों तक की जाए, जहां से पैलेट्स/अयस्क को उद्योगों तक आपूर्ति की जा सके। बचेली में 'बेनिफिकेशन प्लांट, बचेली से नगरनार तक 15 एमटीपीए 'स्लरी पाइपलाइन' और नगरनार में 2 एमटीपीए पैलेट संयंत्र का निर्माण कार्य वित्त वर्ष 2025 तक पूरा होने की संभावना है।

किरंदुल-कोठवलासा (केके) लाइन के दोहरीकरण के माध्यम से निकासी क्षमता में वृद्धि के प्रयास किए जा रहे हैं और यह कार्य पूरे ज़ोरों पर है तथा कार्य पूर्ण किए गए

सेकणों
रेलवे ला
निक्षेप-1
एनएमडी
और छत्ती
जाएगी।

भारत की
की भविष्य

हमारी र
एनएमडी

साथ-सा
पोर्टफो

आकांक्षा

लिंगेसी
विकास

हैनकांक
किया है।

लीगेसी
साथ एक

एनएमडी
प्रथाओं

निगर्गर्ग
पर्यावरण

कंपनी के
करने के

हमारे प्र
बीच सात

दशक में
महत्वाक

मिलियन
देश के ह

एनएमडी
सराहना

स्वास्थ्य
को प्रोत्स

में भी जा

दिव
स्थ

एनएमडी
सराहना

स्वास्थ्य
को प्रोत्स

में भी जा

दिव
स्थ

एनएमडी
सराहना

स्वास्थ्य
को प्रोत्स

में भी जा

दिव
स्थ



श्री अमिताभ मुखर्जी
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)

प्रिय शेयर धारकों,

विश्व में तेजी से हो रहे परिवर्तनों और वैश्विक अनिश्चितताओं का सामना करते हुए एनएमडीसी की उत्कृष्टता, सुस्थिरता और नवाचार के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता दीप्तिमान हो रही है। यद्यपि वित्त वर्ष 2023 ने हमारी सहनशक्ति का परीक्षण करना जारी रखा, परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढालने की हमारी क्षमता और हमारे कार्यबल के असीम समर्पण ने हमें क्षितिज पर उपलब्ध नए अवसरों का लाभ उठाने में अग्रणी बनाए रखा।

विश्व में परिवर्तन हो रहे हैं और उसी प्रकार जिम्मेदार खनन कंपनियों से मांग और अपेक्षाएं भी बदल रही हैं। एक वैश्विक पर्यावरण के अनुकूल खनन कंपनी के रूप में उभरने के लिए हमारा विजन न केवल वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों की सुरक्षा करना भी है। इसी विजन ने हमें अपने लोगों पर पुनः विचार करने के लिए प्रेरित किया। एनएमडीसी का नया लोगो एनएमडीसी 2.0 के रूप में हमारी यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है और सतत एवं जिम्मेदार खनन के लिए हमारी प्रतिबद्धता एवं हमारी वैश्विक आकांक्षाओं को दर्शाता है।

आपके निरंतर समर्थन और भरोसे के साथ, मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में हम जो इतिहास बनाएंगे, वह हमें उस स्थिति में लाने वाले हमारे दृढ़ संकल्प को प्रतिध्वनित करेगा। मुझे इस अवसर पर आप सभी को आपकी उपस्थिति और एक शानदार भविष्य के प्रति हमारे दृष्टिकोण को साझा करने के लिए धन्यवाद देने में प्रसन्नता हो रही है।

में आपको, आपकी कंपनी की वित्त वर्ष 2023 की उपलब्धियों और भविष्य के लिए तैयार किए गए रोडमैप को प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

नई पहचान उच्च आकांक्षाएं असीम संभावनाएं

मुख्यालय: खनिज भवन, मासाब टैंक, हैदराबाद-500028, भारत | www.nmdc.co.in | सीआईएन: L131001

नोट: उपरोक्त कथन का तात्पर्य 07-09-2023 को आयोजित एनएमडीसी की 65वीं एजीएम

ना र

5 आम बैठक

एनएमडीसी



को यातायात हेतु खोल दिया गया है। योजना के अनुसार 150 किलोमीटर इन के दोहरीकरण कार्य में से 84% कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

3 और निक्षेप-14 (ग्रीनफील्ड परियोजनाएँ) के विकास के माध्यम से एनएमडीसी विस्तार की परिकल्पना भी कर रही है, जो कि एनएमडीसी लिमिटेड सगढ़ खनिज विकास निगम (एनसीएल) के संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा की

की स्टील और ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपकी कंपनी अतिमहत्वपूर्ण कच्चे माल की आपूर्ति को सुनिश्चित करने की दिशा में अग्रसर है।

सहायक कंपनी लिगेसी आयरन ओर लिमिटेड, ऑस्ट्रेलिया, जिसमें एनएमडीसी की 90% शेयरधारिता है, इसके माध्यम से हम घरेलू उत्कृष्टता के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत पहचान बना रहे हैं। हमारे गोल्ड लेबो में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और हम विदेशों में खनन करने की हमारी क्षमता को बहुत नजदीक पहुंच गए हैं।

के माउंट बेवन टेनामेंट के संदर्भ में, कंपनी ने अपने मैग्नेटाइट डिपॉजिट के लिए हेनकोक प्रॉस्पेक्टिंग प्राइवेट लिमिटेड की सहायक कंपनी मैग्नेटाइट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम समझौता व्यवहार्यता-पूर्व अध्ययन कार्य पूरी गति से चल रहा है। वर्तमान वर्ष में, एनएमडीसी ने भी उसी टेनामेंट में महत्वपूर्ण खनिजों के विकास के लिए हेनकोक के साथ संयुक्त उद्यम समझौता किया है।

एनएमडीसी जिम्मेदार खनन की जिम्मेदारी लेते हुए अपने ईएसजी और सुस्थिरता के निर्माण के लिए उत्सुक है। पर्यावरण प्रबंधन कार्यक्रमों की व्यापकता और प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन करने के लिए, योग्य और अनुभवी वैज्ञानिक और इंजीनियर हमारी सभी परियोजनाओं में काम कर रहे हैं। इसके लिए विभिन्न पर्यावरणीय और स्थिरता मापदंडों को मापने और रिपोर्ट करने के लिए वैश्विक संगठन कार्य कर रहे हैं।

एनएमडीसी प्राथमिक पर्यावरणीय चिंताओं - जलवायु, जल, जैव विविधता - के समाधान के लिए सामाजिक और शासन संबंधी आयामों का ध्यान रखते हैं। सक्रियता के इस संदर्भ में, एनएमडीसी ने सतत विकास लक्ष्यों और पेरिस समझौते में निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में अपने प्रयासों को बढ़ाया है। उल्लेखनीय पहलों में 3 नए पेड़ लगाना, कार्बन प्रकटीकरण परियोजनाओं का संचालन करना और रिटर्न ऊर्जा में परिवर्तन का समर्थन करना शामिल है।







एनएमडीसी की गहरी सामाजिक चेतना और प्रतिबद्धता की हितधारकों द्वारा की गई है। बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सेवा प्रदान करने और खेल और कला के प्रति समुदाय के प्राकृतिक जुड़ाव को प्रोत्साहित करने में एनएमडीसी दशकों से निवेश कर रहा है, जो वित्त वर्ष 2023 में जारी रहा।

दिनांक: 07.09.2023

स्थान: हैदराबाद

अमिताभ मुखर्जी

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)

संपर्क: 07.09.2023 | हमें संपर्क करें    

हमारी कार्यवाही का रिकॉर्ड नहीं है।

वित्त वर्ष -2023



उत्पादन –
408.17 (एलटी)



बिक्री –
382.23 (एलटी)



नेटवर्थ –
₹22,332 करोड़



टर्नओवर –
₹17,667 करोड़



कर पूर्व लाभ –
₹7,637 करोड़



कर पश्चात लाभ –
₹5,529 करोड़



लाभांश –
660%



जय हिंद

मैं सभी शेयरधारकों, बोर्ड के सदस्यों, कर्मचारियों, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, बैंकों, नियामक निकायों, इस्पात मंत्रालय, राज्य और केंद्र सरकारों और हमारे सभी हितधारकों का आभारी हूँ कि उन्होंने राष्ट्र निर्माण की दिशा में कंपनी की विकास की यात्रा में सहयोग किया।

मिनीमाता महतारी जतन योजना श्रमिक परिवारों के लिए सहारा



मिनी माता महतारी जतन योजना छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत श्रम विभाग की योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। गर्भवती माताओं के लिए संचालित महतारी जतन योजना से बच्चों और माताओं की सेहत की उचित देखभाल भी हो रही है। महासमुंद जिले में मिनी माता महतारी जतन योजना से 2087 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। योजना का लाभ उठाने वाली महासमुंद जिले के सुभाष नगर निवासी श्रीमती प्रमिला यादव ने बताया कि योजना के तहत 20 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि उनके पति छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत रेजा प्रवर्ग में पंजीकृत श्रमिक हैं। प्रमिला ने योजना की सराहना करते हुए कहा कि श्रम विभाग के अंतर्गत मिनी माता महतारी जतन योजना से मिली राशि का उपयोग बच्चों के रहन सहन और उचित देखभाल के लिए किया जा रहा है। श्रमिक परिवार की गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत बड़ा सहारा बन रही है।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गर्भवती महिलाओं को सहायता देने के

लिए मिनी माता महतारी जतन योजना की शुरुआत की गई है। योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को सहायता प्रदान की जाती है। जो भवन निर्माण तथा असंगठित क्षेत्र में निर्माण के कार्य में मजदूरी करती है या जिनके पति मजदूरी करते हैं। उनकी पत्नी को योजना का लाभ दिया जाता है।

पढ़ाई-लिखाई से लेकर इलाज में निर्माण श्रमिकों के लिए बढ़ाई गई सुविधाएं

पढ़ाई-लिखाई से लेकर इलाज में निर्माण श्रमिकों के लिए सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। मंडल की विभिन्न योजनाओं का निर्माण श्रमिकों को लाभ मिल रहा है।

पढ़ाई-लिखाई से लेकर इलाज में निर्माण श्रमिकों के लिए बढ़ाई गई सुविधाएं

पढ़ाई-लिखाई से लेकर इलाज में निर्माण श्रमिकों के लिए सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की विभिन्न योजनाओं का निर्माण श्रमिकों को लाभ मिल रहा है। मंडल की मिनीमाता महतारी जतन योजना में निर्माण श्रमिक के प्रथम दो बच्चों के प्रसव पर एकमुश्त 20 हजार रुपये दिए जा रहे हैं। पिछली सरकार पांच-पांच हजार रुपये करके 10 हजार रुपये देती थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की श्रमिक हितैषी योजना के तहत वर्तमान में प्रदेश में 25 लाख श्रमिक कार्ड बनाए जा चुके हैं। साथ ही कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उद्देश्य यह है

कि असंगठित श्रमिकों के बच्चों, परिवारों को सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से मजबूती मिले। मेधावी छात्र-छात्रा और शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 10वीं-12वीं में छात्र को 5,000 रुपये और छात्रा को 5,500 रुपये की मदद दी जा रही है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं-12वीं में प्राविण्य सूची के प्रथम 10 में आने पर एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।

18 से 21 साल होने पर बेटियों को मदद - मंडल अध्यक्ष ने बताया कि मुख्यमंत्री नोनी सशक्तीकरण सहायता योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिक के दो अविवाहित पुत्रियों को 20-20 हजार रुपये प्रोत्साहन व सहायता राशि मिलेगी। पात्रता के अनुसार लड़की के पिता या माता अथवा दोनों को कम से कम एक वर्ष की अवधि से मंडल में निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। पुत्री की आयु न्यूनतम 18 वर्ष हो तथा 21 वर्ष से अधिक न हो। वह अविवाहित हो और एवं कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। अन्य योजनाओं के माध्यम से भी निर्माण श्रमिकों को लाभ दिया जा रहा है।

दूसरे राज्य से छत्तीसगढ़ आने वाले वाहनों को नवीन पंजीयन चिन्ह प्राप्त करना अनिवार्य



देशभर से यहां राज्य में आने वाले वाहनों के पता परिवर्तन की सूचना दर्ज करते समय छत्तीसगढ़ के लिए नवीन रजिस्ट्रीकरण चिन्ह प्राप्त करने संबंधी प्रक्रिया को वाहन पोर्टल में अनिवार्य किया गया है। अन्य राज्य से एनओसी लेकर आये ऐसे वाहनों, जिसका पूर्व में छत्तीसगढ़ के किसी भी परिवहन कार्यालय में पता परिवर्तन की सूचना दर्ज करा लिये है किन्तु छत्तीसगढ़ राज्य का नवीन पंजीयन चिन्ह प्राप्त नहीं किये है। ऐसे समस्त वाहन स्वामी छत्तीसगढ़ राज्य हेतु नवीन पंजीयन चिन्ह प्राप्त करने के लिए वाहन पोर्टल के माध्यम से विहित शुल्क का ऑनलाईन भुगतान कर आवश्यक दस्तावेज सहित वाहन का भौतिक सत्यापन कराते हुये संबंधित परिवहन कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ताकि प्रस्तुत आवेदन पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही किया जा सके। अन्यथा ऐसे वाहनों पर मोटरयान अधिनियम एवं नियमों के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

वाहन पोर्टल द्वारा भौतिक सत्यापन कराकर प्राप्त करें नवीन पंजीयन चिन्ह

एनआईसी द्वारा विकसित वाहन पोर्टल के माध्यम से राज्य में वाहन संबंधी समस्त कार्य संपादित किये जा रहे हैं। जिसके तहत अन्य राज्य के वाहनों को पता परिवर्तन की सूचना दर्ज करने के साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य का नवीन रजिस्ट्रीकरण चिन्ह जारी हो रहे हैं। किन्तु राज्य में वाहन पोर्टल लागू होने के पहले अन्य राज्य से आने वाली वाहनों का केवल पता परिवर्तन की सूचना दर्ज है, जिसमें से विभिन्न वाहनों का छत्तीसगढ़ राज्य के लिए नवीन रजिस्ट्रीकरण चिन्ह प्राप्त नहीं हुआ है।

परिवहन मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अन्य राज्य के ऐसे वाहन जिनका पता परिवर्तन की सूचना पूर्व में छत्तीसगढ़ के किसी परिवहन कार्यालय द्वारा दर्ज कर लिया गया है किन्तु छत्तीसगढ़ राज्य का नवीन पंजीयन चिन्ह समनुदेशित नहीं किया गया है, ऐसे वाहनों का केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 54 तथा छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994 के नियम 55 अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के लिए नवीन रजिस्ट्रीकरण चिन्ह समनुदेशित करने की कार्यवाही किया जाना है।



भारत मंडपम में नटराज की सबसे ऊंची प्रतिमा

इसी के साथ मुख्य आयोजन स्थल भारत मंडपम परिसर में शिव-नटराज की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। शिव नटराज की यह मूर्ति अनंत शक्ति का प्रतीक है। ईश्वर का यह स्वरूप धर्म, दर्शन, कला, शिल्प और विज्ञान का समन्वय है। मुख्य आयोजन स्थल होने की वजह भारत मंडपम पर दुनियाभर की निगाहें हैं। इस तरह देश ने अब जता दिया है कि समृद्धि के पथ पर अग्रसर भारत अब बड़ा ही करेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश नित नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। पीएम मोदी ने देशवासियों में ऐसा आत्मविश्वास जगाया है कि अब वे उनकी प्रेरणा से छोटी सफलताओं से खुश नहीं होते। अब वे कुछ बड़ा करना चाहते हैं। यही वजह है कि भारत के नाम नए-नए रिकार्ड दर्ज हो रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। यह पीएम मोदी की प्रेरणा ही है कि आज भारत के नाम दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म, सबसे ऊंची प्रतिमा, सबसे लंबी हाईवे टनल, सबसे ऊंचा रेल ब्रिज, सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट, सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग, देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर और नटराज की सबसे ऊंची प्रतिमा का रिकार्ड दर्ज हो चुका है।

भारत मंडपम में नटराज की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा

भारत मंडपम में लगाई गई नटराज की यह मूर्ति दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई 27 फीट और चौड़ाई 21 फीट है। वहीं इस मूर्ति का वजन लगभग 18 टन है। इस मूर्ति को लॉस्ट वैक्स तकनीक के माध्यम से अष्टधातु से बनाया गया है। इस मूर्ति का निर्माण श्री राधाकृष्णन की अगुआई में शिल्प शास्त्र में लिखे गए सभी नियमों और सिद्धांतों का पालन करते हुए किया गया है। इस प्रतिमा को जिस लॉस्ट वैक्स तकनीक के माध्यम से बनाया गया है, उसका पालन चोल काल से किया जा रहा है। शिव नटराज की यह मूर्ति अनंत शक्ति का प्रतीक है। ईश्वर का यह स्वरूप धर्म, दर्शन, कला, शिल्प

और विज्ञान का समन्वय है।

चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना भारत

चंद्रयान-3 14 जुलाई 2023 को 41 दिन की चंद्रमा की यात्रा पर खाना हुआ था और 23 अगस्त 2023 को इसने सफल 'सॉफ्ट लैंडिंग' की। इसके साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। इसके साथ ही चंद्रमा की सतह पर सफल 'सॉफ्ट लैंडिंग' करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। भारत से पहले चांद पर पूर्ववर्ती सोवियत संघ, अमेरिका और चीन ही सफल 'सॉफ्ट लैंडिंग' कर पाए हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से कोई भी देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 'सॉफ्ट लैंडिंग' नहीं कर पाया है, और अब भारत के नाम इस उपलब्धि को हासिल करने का रिकार्ड हो गया है। 4 साल में भारत के दूसरे प्रयास में चंद्रमा पर चंद्रयान-3 के लैंडर 'विक्रम' ने 26 किलोग्राम के रोवर 'प्रज्ञान' के साथ योजना के मुताबिक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में सफलतापूर्वक 'सॉफ्ट लैंडिंग' की। इस तरह इस टेक्नोलॉजी में भारत ने महारत हासिल कर ली और इसको लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है।

ITPO कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स दुनिया के टॉप 10 कॉम्प्लेक्स में शामिल

दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत का ITPO कॉम्प्लेक्स दुनिया के टॉप 10 कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स में शामिल हो गया है। यह जर्मनी के हनोवर एजीबिशन सेंटर और शंघाई के नेशनल एजीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर को टक्कर देता है। यह कॉम्प्लेक्स ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक सिडनी ओपेरा हाउस से अधिक बड़ा है। ओपेरा हाउस में जहां तकरीबन 5,500 लोगों के बैठने की व्यवस्था है वहीं ITPO कॉम्प्लेक्स में 7,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। इस तरह यह जर्मनी के हनोवर एजीबिशन सेंटर और शंघाई के नेशनल एजीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर को टक्कर देता है। इस कन्वेंशन सेंटर को वैश्विक पैमाने पर बड़े सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए उपयुक्त स्थान बनाती है।



“Life Is Finished Here”: How Deadly Morocco Earthquake Wiped Out A Village

It was delicate work for the searchers to remove the woman's body from the rubble of a village that effectively ceased to exist in Morocco's deadliest earthquake in over six decades.

Her 25-year-old fiance Omar Ait Mbarek watched the digging Sunday with his eyes red and full of tears, and surrounded by onlookers, just kilometres from the quake epicentre in the Atlas Mountains.

He was on the phone with her when the shaking started late Friday and he heard kitchen utensils crash to the floor before the line cut out. He knew she was gone.

"What do you want me to say? I'm wounded," he told AFP after Mina Ait Bihi, weeks from becoming his wife, was carried away in blankets to a makeshift cemetery that already held 68 others.

The men who had carefully used their hands to scoop away the dirt that covered her also found her phone and handed it over to the grieving man.

All around him the village of Tikht, previously home to at least 100 families, was a tangle of timbers, chunks of masonry as well as broken plates, shoes and the occasional intricately patterned rug.

"Life is finished here," said Mohssin Aksum, 33, who had family living in the tiny settlement. "The village is dead."

Traditionally built homes

Like many of the hardest-hit villages, it was a small rural place with a significant number of buildings constructed with a traditional mix of stone, timber and a mortar composed of mud.

Dozens of residents, mourning relatives and soldiers were gathered at the ruins. Several said they couldn't remember any previous earthquake in the area.

"It wasn't something people here thought about when building their houses," said 23-year-old student Abdelrahman Edjal, who lost most of his family in the disaster.

But the quality of the building materials was not uppermost in his mind as he sat on a boulder among the rubble under the

strikingly blue sky and surrounded by mountains.

He had gone out for a walk after dinner when the shaking began, and saw people trying to escape their collapsing houses.

He pulled his own father from the ruins of the family home, but the injuries were too serious. He died with his son close by.

Twisted steel reinforcement rods poked out of the debris in Tikht, so clearly some more recent building techniques were part of the local structures.

Daily life was already hard in the area, which is a roughly two-hour drive from the jobs that Marrakesh's massive tourist industry can offer.

'Less than nothing'

Aksum, who has local roots but lives in Rabat, said the quake has taken away the little bit that people had.

As he spoke, he gestured to his nose, and said the livestock that had been kept by locals was now buried under the debris and beginning to rot. "Now, people have less than nothing," he noted.

AFP

आर्थिक तरक्की

भारत की जीडीपी ने सारे ग्लोबल इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स के अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए अप्रैल-जून में 4 तिमाहियों की सबसे तेज ग्रोथ दर्ज की है। इसके बाद इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने मजबूत आर्थिक गति के चलते 2023 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत की वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर शुक्रवार को 6.7 प्रतिशत कर दिया।

मूडीज ने अपने ग्लोबल मैक्रो आउटलुक में कहा, मजबूत सेवाओं के विस्तार तथा पूंजीगत व्यय ने भारत की दूसरी (अप्रैल-जून) तिमाही में एक साल पहले की तुलना में 7.8 प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि को प्रेरित किया। इसलिए हमने भारत के लिए अपने 2023 कैलेंडर वर्ष के वृद्धि का अनुमान 5.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.7 प्रतिशत कर दिया है।

रेटिंग एजेंसी का यह है अनुमान

रेटिंग एजेंसी ने कहा कि दूसरी तिमाही का बेहतर प्रदर्शन 2023 में उच्च आधार प्रदान करता है। हमने अपना 2024 का वृद्धि अनुमान 6.5 प्रतिशत से घटाकर 6.1 प्रतिशत कर दिया है। वहीं, इससे पहले मूडीज ने स्टेबल आउटलुक के साथ भारत की साख को बीएएए3 रेटिंग पर बरकरार रखा था। इस रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि घरेलू मांग के दम पर भारत की आर्थिक वृद्धि दर अगले 2 साल तक जी20 देशों की अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले ऊंचे स्तर पर बनी रहेगी।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने कल जीडीपी के आंकड़े जारी किए थे, जिसमें 2023-24 की पहली तिमाही अप्रैल-जून में विकास दर 7.8 फीसदी रही है। खास बात है कि यह 4 तिमाहियों में सबसे ज्यादा रही है। इससे पहले ज्यादातर अर्थशास्त्रियों ने जीडीपी ग्रोथ रेट 7.7 फीसदी तक रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन वास्तविक आंकड़ा इस अनुमान से बेहतर रहा।

महंगाई के बीच आर्थिक विकास की इस बेहतर दर के पीछे उपभोक्ता खपत रही, जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जबरदस्त सपोर्ट मिला। अप्रैल-जून तिमाही में निर्माण क्षेत्र की ग्रोथ रेट 7.9 फीसदी रही। इसी तरह, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 4.7 फीसदी रही, जो जनवरी-मार्च तिमाही में 4.5 फीसदी और पिछले साल अप्रैल-जून में 6.1 फीसदी थी।

दुनिया इस समय मंदी की चपेट में हैं। अमेरिका जैसे विकसित देशों की अर्थव्यवस्था मंदी का सामना कर रही है। इनके विकास दर में गिरावट आ रही है और महंगाई चरम पर है। ऐसी स्थिति में भारत एक चमकता हुआ सितारा बन गया है। इसकी पुष्टि एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) के एशियन डेवलपमेंट आउटलुक अपडेट में की गई है। इसमें भारत की विकास दर का अनुमान 2023-24 के लिए 6.4 प्रतिशत और 2024-25 के लिए पहले की तरह 6.7 प्रतिशत बरकरार रखा गया है। इस दौरान भारत का विकास दर चीन से अधिक रहेगा।

2075 तक भारत बनेगा दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था- गोल्डमैन सैश

भारत फिलहाल दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अमेरिका, जापान, चीन, जर्मनी से पीछे है, लेकिन भारत तेजी से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। गोल्डमैन सैश की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2075 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार भारत जापान, जर्मनी और अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। गोल्डमैन सैश के रिसर्च इकोनॉमिस्ट शांतनु सेनगुप्ता के मुताबिक भारत की आबादी में दुनिया की आबादी की तुलना में सबसे बेहतरीन मिश्रण मौजूद है। कामगारों, बच्चों और बुजुर्गों की आबादी भारत में अन्य देशों की तुलना में सबसे अच्छी है। इस कारण भारत मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ सकता है। उन्होंने यह भी कहा



कि भारत ने तकनीक और अनुसंधान के क्षेत्र में अन्य देशों की तुलना में कहीं बेहतर काम किया है। ये दोनों ही क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा कैपिटल निवेश भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद कर रहा है।

2023-24 में 6.5 प्रतिशत रहेगी जीडीपी ग्रोथ रेट- आरबीआई

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। देश की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2023-24 में 6.5 प्रतिशत की दर से आगे बढ़ेगी। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिशाली दास ने मौजूदा वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान बताया है। गवर्नर दास ने कहा कि हमने सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। हमें इसको हासिल करने की पूरी उम्मीद है। उन्होंने कहा कि जीडीपी वृद्धि दर को लेकर हमने संतुलित रख लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि हालांकि, वैश्विक स्तर पर कमजोर मांग, वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता, लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तनाव और अल नीनो प्रभाव की आशंका से जोखिम भी है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, 2023-24 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहने का संभावना है। रिजर्व बैंक ने इस महीने पेश मौद्रिक नीति समीक्षा में भी जीडीपी वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहने के अनुमान को बरकरार रखा है।

फिच रेटिंग्स ने बढ़ाया भारत की जीडीपी का अनुमान

वैश्विक आर्थिक मंदी के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है। ग्लोबल एजेंसी फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.3 प्रतिशत कर दिया।

फिच ने विकास का अनुमान वित्त वर्ष 2023 के 7.2 प्रतिशत को देखते हुए किया है। फिच ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था व्यापक रूप से मजबूत है। 2023 की पहली

तिमाही (जनवरी-मार्च) में यह सालाना आधार 6.1 प्रतिशत की दर से बढ़ी है। हाल के महीनों में वाहन बिक्री के आंकड़े बेहतर रहे हैं। इसके अलावा पीएमआई सर्वे और ऋण की वृद्धि भी मजबूत रही है। इसके चलते चालू वित्त वर्ष के लिए हमने वृद्धि दर के अनुमान को 0.3 प्रतिशत बढ़ाकर 6.3 प्रतिशत कर दिया है। इसके साथ ही फिच ने कहा कि 2024-25 और 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

वैश्विक मंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर नहीं- फिच

रेटिंग एजेंसी फिच ने इसके पहले भारत की संप्रभु रेटिंग के परिदृश्य को स्थिर बताते हुए कहा कि देश का विकास मजबूत दिख रहा है। फिच रेटिंग्स ने भारत की दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा जारीकर्ता डिफॉल्ट रेटिंग को स्थिर परिदृश्य के साथ 'बीबीबी' के स्तर पर रखा है। फिच ने कहा कि भारत की रेटिंग अन्य देशों की तुलना में मजबूत ग्रोथ और बाहरी वित्तीय लचीलापन दर्शा रही है, जिससे अर्थव्यवस्था को पिछले साल के बड़े बाहरी झटकों से पार पाने में मदद मिली है।

FY 23-24 में भारत की ग्रोथरेट हो सकती है 6.5 प्रतिशत से अधिक

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था रूस-यूक्रेन संकट और कोरोना महामारी काल में भी मजबूत बनी हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की ग्रोथरेट 6.5 प्रतिशत से अधिक हो सकती है। टाटा कैपिटल के एमडी और सीईओ राजीव सभरवाल ने कहा है कि सभी इकॉनॉमिक इंडिकेटर्स बताते हैं कि FY 23-24 में भारत की ग्रोथरेट 6.5 प्रतिशत से अधिक हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि इंडियन इकॉनॉमी लंबी अवधि में हर साल 7.5 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। राजीव सभरवाल ने कहा कि उन्हें व्यक्तिगत तौर पर यह भी लगता है कि ये ग्रोथ 6.75 प्रतिशत तक रह सकती है।

वित्त वर्ष 2023-24 में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था- विश्व बैंक विश्व बैंक का कहना है कि भारत सबसे बड़े उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सकल और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) दोनों के मामले में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। विश्व बैंक ने कहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.3 प्रतिशत रहेगी। विश्व बैंक ने वैश्विक आर्थिक संभावनाओं पर अपनी ताजा रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उभरती हुई प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) में भारत कुल मिलाकर और प्रति व्यक्ति जीडीपी दोनों में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। विश्व बैंक ने कहा कि भारत में निजी उपभोग और निवेश में अप्रत्याशित जुझारूपन देखने को मिल रहा है। साथ ही सेवाओं की वृद्धि भी मजबूत है। अपनी ताजा रिपोर्ट में विश्व बैंक ने कहा है कि 2023 में वैश्विक वृद्धि दर 2.1 प्रतिशत रहेगी, जो इससे पहले 2022 में 3.1 प्रतिशत रही थी। इसके साथ ही साथ ही यह भी कहा है कि चीन के अलावा उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) में वृद्धि दर इस वर्ष 2.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

भारत 'ब्राइट स्पॉट' के रूप में बरकरार, 2024 में 6.7 प्रतिशत रहेगी वृद्धि दर संयुक्त राष्ट्र (United Nations) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 'ब्राइट स्पॉट' के रूप में बरकरार है। यूएन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में कई सकारात्मक चीजें दिख रही हैं और यह कैलेडर वर्ष 2024 में 6.7 प्रतिशत की रफ्तार से आगे बढ़ सकती है। रिपोर्ट के अनुसार घरेलू मांग में लचीलापन बरकरार रहने से भारतीय अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग में वैश्विक आर्थिक निगरानी शाखा, आर्थिक विश्लेषण और नीति प्रभाग के प्रमुख हामिद राशिद ने कहा है कि हम इस साल के लिए अपने पूर्वानुमान को लेकर काफी आश्वस्त हैं।

वित्तवर्ष 23-24 में 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था मौजूदा वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी ने कहा है कि कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद विकास दर 6.5 प्रतिशत रहेगी। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि अमेरिका और यूरोपीय बैंकिंग संकट का भारत के वित्त क्षेत्र पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

वैश्विक अर्थव्यवस्था में चीन, भारत मिलकर करेंगे आधा योगदान चीन के अग्रणी शोध संस्थान 'बाओ फोम फॉर एशिया' (बीएफए) ने 28 मार्च, 2023 को जारी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि 2023 में एशियाई अर्थव्यवस्थाएं दुनिया के समग्र आर्थिक पुनरुद्धार की रफ्तार को बनाए रखे हुए हैं। इस साल की ग्रोथ में भारत और चीन मिलकर करीब आधा योगदान देंगे जिससे एशिया 'असाधारण प्रदर्शन' करने वाला महाद्वीप बनकर उभरेगा। 'एशियाई आर्थिक परिदृश्य एवं एकीकरण में प्रगति' शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा गया है कि भारत और चीन इस साल वैश्विक आर्थिक वृद्धि में मिलकर आधा योगदान देने वाले हैं। इस तरह एशियाई अर्थव्यवस्थाएं वर्ष 2023 में समग्र आर्थिक वृद्धि को तेज करने में प्रमुख इंजन बनी हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2023 में एशिया की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर वर्ष 2022 के 4.2 प्रतिशत से बढ़कर 4.5 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है।

सात प्रतिशत रहेगी भारत की विकास दर- एक्यूडट

दुनिया भर के सभी अंतरराष्ट्रीय संगठन और अर्थशास्त्री भारत की आर्थिक तरक्की का लोहा मान रहे हैं। तमाम सभी अंतरराष्ट्रीय संगठनों का कहना है कि भारत आने वाले समय में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक्यूडट रेटिंग्स एंड रिसर्च ने भी वित्त वर्ष 23 में सकल घरेलू उत्पाद-जीडीपी की वृद्धि दर 7 प्रतिशत रहने की बात कही है। एक्यूडट ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा कि वित्त वर्ष 23 में जीडीपी वृद्धि दर 7 प्रतिशत और वित्त वर्ष 24 में 6 प्रतिशत रहने का अनुमान है। एजेंसी ने कहा कि भारत की औद्योगिक विकास दर में वृद्धि हुई है। उद्योग उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में भी मजबूती देखी गई है।

भारत की विकास दर पूरी दुनिया में होगी सबसे तेज

पूरे विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था का डंका बज रहा है। विदेशी उद्योगपति और निवेशक भी भारत के आर्थिक विकास का लोहा मान रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 में भारत के आर्थिक सुधारों की तारीफ करते हुए अमेरिका के मशहूर निवेशक रे डालियो ने कहा कि भारत की विकास दर पूरी दुनिया में सबसे तेज होगी। अमेरिकी कारोबारी डेलियो ने 'सरकार और बदलती विश्व व्यवस्था' सत्र के दौरान इस बात पर जोर दिया कि भारत आने वाले वर्षों में सबसे ज्यादा तरक्की करेगा। उन्होंने कहा कि भारत का भविष्य उज्ज्वल है। मोदी सरकार में हुए सुधारों की तारीफ करते हुए डालियो ने कहा कि एक दशक में दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत में सबसे तेज और बड़े बदलाव हुए हैं। अब भी तेज रफ्तार से बदलाव जारी हैं। पिछले 10 वर्षों के अध्ययन से और जो हम देश के लिए देख रहे हैं उसके आधार पर, भारत में सबसे बड़ी और सबसे तेज विकास दर होगी।

2030 तक विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेगा भारत

स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (World Economic Forum) 2023 में वैश्विक कंसल्टेंसी फर्म ईवाई द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध और वैश्विक आर्थिक संकट का सामना करने के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था साल 2028 में 5 लाख करोड़, 2036 में 10 लाख करोड़ के पड़ाव को पार करते हुए साल 2047 तक 26 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगी। वहीं प्रति व्यक्ति सालाना औसत आय बढ़कर छह गुना हो जाएगी। वैश्विक कंसल्टेंसी फर्म ईवाई द्वारा 'इंडिया एट 100 : रीयल्टीजिंग द पोर्टेंशियल ऑफ 26 ट्रिलियन इकॉनॉमी' नाम से पेश रिपोर्ट में दावा किया गया कि 2030 तक भारत जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन चुका होगा। 6 प्रतिशत की सालाना औसत वृद्धि दर के आधार पर आंकलन किया गया कि 2047 में प्रति व्यक्ति सालाना औसत आय 15 हजार डॉलर यानी मौजूदा विनिमय दर के लिहाज से करीब 12.25 लाख रुपये पहुंच जाएगी, यह आज के स्तर से 6 गुना से अधिक होगी।

पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टरप्लान

भारत ने जॉर्जिया के त्बिलिसी में एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा आयोजित '2023 क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण सम्मेलन: आर्थिक गलियारा विकास (ईसीडी) के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण को मजबूत करना' में पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को प्रदर्शित किया। 5 से 7 सितंबर, 2023 तक आयोजित सम्मेलन में 30 से अधिक सदस्य देशों की भागीदारी देखी गई, जिनमें ईसीडी के लिए जिम्मेदार एडीबी के विकासशील सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी, विकास भागीदार एजेंसियों और क्षेत्रीय सहयोग संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) की विशेष सचिव (लॉजिस्टिक्स) सुश्री सुमिता डावरा ने किया।

सम्मेलन का उद्देश्य था (i) ईसीडी के साथ स्थानिक परिवर्तन/क्षेत्र-केंद्रित दृष्टिकोण को एकीकृत करने के तरीकों का पता लगाना तथा व्यापक दृष्टिकोण के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना एवं (ii) निवेश योग्य परियोजनाओं पर आर्थिक गलियारा विकास (ईसीडी) फ्रेमवर्क के अनुप्रयोग और परिचालन दिशानिर्देशों पर ज्ञान साझा करना।

सुश्री डावरा ने सम्मेलन को बताया कि पीएम गतिशक्ति - मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान एक मेड इन इंडिया पहल है, जो आर्थिक गतिविधियों और सामाजिक अवसरचना के लिए मल्टी-मॉडल इन्फ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी की एकीकृत योजना के लिए एक परिवर्तनकारी 'संपूर्ण-सरकारी' दृष्टिकोण है, जिससे लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार होगा। पीएम गति शक्ति के सिद्धांत क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के हिस्से के रूप में सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र-आधारित विकास पर आधारित हैं। उन्होंने भारत सरकार के लक्षित कार्यक्रमों, अवसरचना निवेश के लिए भारी पूंजीगत व्यय और संपूर्ण लॉजिस्टिक्स तथा अवसरचना के इकोसिस्टम को बदलने की दिशा में भू-स्थानिक और अन्य अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने का उल्लेख किया।

उन्होंने एकीकृत अवसरचना की एकीकृत योजना तैयार करने के लिए जीआईएस डेटा-आधारित 'संपूर्ण सरकार' के दृष्टिकोण, पीएम गतिशक्ति को प्रदर्शित किया। क्षेत्रीय सहयोग के लिए अपने ईसीडी फ्रेमवर्क के दायरे को व्यापक बनाने पर विचार-मंथन के लिए, एडीबी द्वारा विश्व स्तर के अग्रणी विशेषज्ञों को एक साथ लाया गया था। विशेष सचिव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत ने क्षेत्र-आधारित अवसरचना विकास के लिए परिवर्तनकारी दृष्टिकोण, पीएम गतिशक्ति को पहले ही क्रियान्वित कर दिया है और सफलतापूर्वक लागू कर रहा है। इसलिए यह न केवल अवसरचना की कनेक्टिविटी का निर्माण कर रहा है,



बल्कि अपने साथ आर्थिक और सामाजिक विकास भी ला रहा है, जिससे व्यापार करने में आसानी होगी और जीवन यापन में आसानी होगी।

पीएम गतिशक्ति एनएमपी 1400 से अधिक डेटा परतों और 50+ उपकरणों के साथ एक जीआईएस डेटा-आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो मुख्य और उपयोगिता आधारित अवसरचना, भूमि उपयोग, मौजूदा संरचनाओं (जैसे, पुल, रेलवे क्रॉसिंग, एक पुलिया), मिट्टी की गुणवत्ता, निवास स्थान का फैलाव, पर्यटन स्थल, वन-संवेदनशील क्षेत्र इत्यादि एवं स्थल उपयुक्तता जैसे डेटा आधारित निर्णय के लिए दृश्य चित्रण प्रस्तुत करता है। इसकी संस्थागत व्यवस्था केंद्र और राज्य स्तर पर पूरी तरह से संचालन में है, जिससे योजना निर्माण और फैसले लेने के क्रम में पीएम गतिशक्ति सिद्धांतों को अपनाने में सुविधा होती है।

उन्होंने कहा कि पीएम गतिशक्ति के तहत महत्वपूर्ण

परियोजना स्थलों/औद्योगिक समूहों/पर्यटन स्थलों/सामाजिक क्षेत्र की परिसंपत्तियों के आसपास के प्रभाव क्षेत्रों को परिपूर्ण करने के लिए एक स्थानिक/क्षेत्र आधारित समग्र विकास दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। विनिर्माण मूल्य श्रृंखला, लॉजिस्टिक्स सुविधाएं, स्कूल और अस्पताल जैसे सामाजिक क्षेत्र के संस्थान, कौशल केंद्र को एकीकृत करने के लिए कनेक्टिविटी अवसरचना की आवश्यकताओं का आकलन योजना स्तर पर किया जाता है और तदनुसार स्थानिक योजनाएं विकसित की जाती हैं। पीएम गतिशक्ति दृष्टिकोण पड़ोसी देशों के बीच क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और निर्बाध व्यापार को मजबूत करने की दिशा में देश के भीतरी इलाकों के मल्टी मॉडल गलियारे जैसे औद्योगिक सड़क गलियारे, समर्पित रेल माल ढुलाई गलियारे और जलमार्ग नेटवर्क के प्राकृतिक विस्तार की सुविधा प्रदान कर रहा है।

प्रत्येक बच्चे की विशेष क्षमताओं को पहचानना और उन क्षमताओं को विकसित करने में बच्चे की मदद करना शिक्षकों के साथ-साथ माता-पिता का भी कर्तव्य है: राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू



देश भर के शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 सितंबर, 2023 शिक्षक दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन, नई दिल्ली में हुए एक समारोह में देश भर के शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान; राज्य मंत्री, शिक्षा मंत्रालय श्रीमती अन्नपूर्णा देवी; राज्य मंत्री, शिक्षा मंत्रालय डॉ. सुभाष सरकार; राज्य मंत्री, शिक्षा मंत्रालय डॉ. राजकुमार रंजन सिंह; इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव चन्द्रशेखर; सचिव, उच्च शिक्षा श्री के. संजय मूर्ति; सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग श्री संजय कुमार; सचिव, एमएसडीई श्री अतुल कुमार तिवारी भी उपस्थित रहे।

इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि हर किसी के जीवन में प्राथमिक शिक्षा का सबसे ज्यादा महत्व है। उन्होंने कहा कि कई शिक्षाविद् बच्चों के संतुलित विकास के लिए 3-एच फॉर्मूले की बात करते हैं जिसमें पहला एच हार्ट यानी हृदय, दूसरा एच हेड यानी सिर और तीसरा एच हैंड यानी हाथ है। उन्होंने बताया कि हृदय का संबंध संवेदनशीलता, मानवीय मूल्यों, चरित्र की मजबूती और नैतिकता से है। उन्होंने कहा कि सिर या मस्तिष्क का संबंध मानसिक विकास, तर्क शक्ति और पढ़ने से है और हाथ का संबंध शारीरिक कौशल और शारीरिक श्रम के प्रति सम्मान से है। उन्होंने कहा कि ऐसे समग्र दृष्टिकोण पर बल देने से ही बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव होगा।

राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षण पेशे में महिलाओं की भागीदारी को देखते हुए शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला शिक्षकों की संख्या अधिक होनी चाहिए। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए छात्राओं और शिक्षकों को प्रोत्साहित किए जाने के महत्व पर भी जोर दिया।

राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करते हैं। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को हर बच्चे का मौलिक अधिकार माना जाता है और इन लक्ष्यों को हासिल करने में शिक्षकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र-निर्माता के रूप में शिक्षकों के महत्व का उल्लेख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी स्पष्ट रूप से किया गया है।

राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षकों के साथ-साथ माता-पिता का भी यह कर्तव्य है कि वे प्रत्येक

बच्चे की विशेष क्षमताओं को पहचानें और संवेदनशीलता के साथ उन क्षमताओं को विकसित करने में बच्चे की मदद करें। उन्होंने कहा कि हर माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे पर विशेष ध्यान दिया जाए और प्यार से व्यवहार किया जाए। माता-पिता बड़े विश्वास के साथ अपने बच्चों को शिक्षकों को सौंपते हैं। उन्होंने कहा कि कक्षा में बच्चों के बीच प्यार बांटने का अवसर मिलना प्रत्येक शिक्षक के लिए बहुत सौभाग्य की बात है।

राष्ट्रपति ने कहा कि हर कोई अपने शिक्षकों को याद करता है। उन्होंने कहा कि बच्चों को शिक्षकों से जो प्रशंसा, प्रोत्साहन या सजा मिलती है वह उनकी यादों में रहती है। उन्होंने कहा कि अगर बच्चों में सुधार लाने के इरादे से उन्हें सजा दी जाती है तो उन्हें इसका एहसास बाद में होता है। उन्होंने कहा कि बच्चों को ज्ञान देने से ज्यादा जरूरी है उन्हें प्यार और स्नेह देना।

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का उद्देश्य देश में शिक्षकों के अद्वितीय योगदान का उत्सव मनाना और उन शिक्षकों को सम्मानित करना है जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और समर्पण के माध्यम से न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी समृद्ध बनाया है। प्रत्येक पुरस्कार में प्रमाण पत्र, 50,000 रुपये का नकद पुरस्कार और एक रजत पदक दिया जाता है। पुरस्कार विजेताओं को माननीय प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करने का भी अवसर मिलता है।

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय एक कठोर, पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने के लिए हर साल शिक्षक दिवस पर एक राष्ट्रीय स्तर का समारोह आयोजित करता रहा है। इस वर्ष से, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का दायरा बढ़ाकर उच्च शिक्षा विभाग और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के शिक्षकों को इसमें शामिल कर लिया गया है। इस वर्ष 50 स्कूल शिक्षकों, उच्च शिक्षा से जुड़े 13 शिक्षकों और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय से 12 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। नई तरह से शिक्षण, अनुसंधान, सामुदायिक पहुंच और काम की नवीनता को पहचानने के उद्देश्य से अधिकतम भागीदारी (जनभागीदारी) सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन मोड में नामांकन मांगे गए थे। शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों के चयन के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों को शामिल करते हुए तीन अलग-अलग स्वतंत्र राष्ट्रीय जूरी का गठन किया था।

सूर्य देव को समर्पित कोणार्क मंदिर



कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा के मध्ययुगीन वास्तुकला का एक सर्वश्रेष्ठ नमूना है। इस मंदिर को कलिंग वास्तुकला की उपलब्धि का सर्वोच्च बिंदु माना जाता है क्योंकि इस प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की वास्तुकला काफी हद तक कलिंगा मंदिर की वास्तुकला से मिलती-जुलती है।

उड़ीसा के पूर्वी समुद्र तट पुरी के पास स्थित इस कोणार्क सूर्य मंदिर की संरचना और इसके पत्थरों से बनी मूर्तियां कामोत्तेजक मुद्रा में हैं, जो इस मंदिर की अन्य विशेषताओं को बेहद शानदार ढंग से दर्शाती हैं। एक विशाल रथ के आकार में बने कोणार्क सूर्य मंदिर

में करीब 12 जोड़े विशाल पहिए लगे हुए हैं, जिसे करीब 7 ताकतवर घोड़े खींचते प्रतीत होते हैं। वहीं यह पहिए धूप-घड़ी का काम करते हैं और इनकी छाया से समय का अनुमान लगाया जाता है।

आपको बता दें कि इस मंदिर के 7 घोड़े हफ्ते के सभी सातों दिनों के प्रतीक माने जाते हैं, जबकि 12 जोड़ी पहिए दिन के 24 घंटों को प्रदर्शित करते हैं। इसके साथ ही इनमें लगभग 8 ताड़ियां दिन के आठों प्रहर को दर्शाती हैं। काले ग्रेनाइट और लाल बलुआ पत्थर से बना यह एकमात्र ऐसा सूर्यमंदिर है, जो कि इसकी खास बनावट और भव्यता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इस

अद्भुत मंदिर के निर्माण में कई कीमती धातुओं का इस्तेमाल किया गया है। इस सूर्य मंदिर में सूर्य भगवान की बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में बनी तीन-अलग-अलग मूर्तियां भी बनी हुई हैं, जिन्हें उदित सूर्य, मध्याह्न सूर्य और अस्त सूर्य भी कहा जाता है।

इस मंदिर को इसकी खूबसूरत कलाकृति और अनूठी वास्तुशिल्प के लिए यूनेस्को (UNESCO) की वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया गया है। कोणार्क सूर्य मंदिर के मुख्य प्रवेशद्वार पर शेरों द्वारा हाथियों के विनाश का दृश्य अंकित है, जिसमें शेर घमंड, अहंकार और हाथी धन का प्रतीक माना जाता है।

पाकिस्तान में शरण लेने वाले आतंकियों की संपत्ति जब्त



जम्मू कश्मीर में आतंक को लेकर सरकार लगातार ठोस कदम उठाते जा रही है। इसी बाबत पुलिस ने 400 से अधिक पाकिस्तान में रहने वाले कश्मीरी आतंकवादियों और उनके समर्थकों की संपत्ति जब्त की है। पुलिस ने बताया कि आने वाले दिनों में ये कार्रवाई और भी तेज होगी। अभी 300 से अधिक पाक में छुपे भगोड़े आतंकियों की संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा। पुलिस के पास उन सभी आतंकवादियों की एक सूची है। जो जम्मू-कश्मीर के मूल निवासी हैं और जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में सक्रिय थे लेकिन अब शरण लेने के लिए पाकिस्तान भाग गए हैं। उनकी संपत्तियां जब्त की जा रही हैं और यह प्रक्रिया जारी रहेगी।

भगोड़ों आतंकियों पर हो रही कार्रवाई

जम्मू-कश्मीर की जांच एजेंसी SIA और CID ने सामूहिक तौर पर भगोड़ों आतंकियों की तलाश का

अभियान छेड़ रखा है। भगोड़ों की कुल तादाद 734 बताई जा रही है। इनमें से 80 भगोड़ों की मौत हो चुकी है, जबकि 4 जेल में बंद हैं। वहीं में जिन 369 भगोड़ों का वेरिफिकेशन हो चुका है उनकी प्रॉपर्टिज भी जब्त की जाएगी।

अलगाववादी नेता और टॉप मिलिटेंट कमांडर्स की प्रॉपर्टिज की गई अटैच - जम्मू कश्मीर में अब तक जो प्रॉपर्टी अटैच की गई है। इनमें कई बड़े अलगाववादी नेता और टॉप मिलिटेंट कमांडर्स का नाम भी शामिल है। इनमें 190 से ज्यादा आतंकी जिसमें सबसे ज्यादा डोडा रिजिन से हैं, इनकी संख्या 125 है। वहीं, 36 किस्तावार, 18 राजौरी पुंछ के और बाकी श्रीनगर अनंतनाग और कुपवाड़ा से है। आतंकियों के साथ-साथ जमात-ए-इस्लामी और अलगाववादी नेताओं के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की गई है। हुर्रियत कांफ्रेंस के पूर्व चेयरमैन सैयद अली

शाह गिलानी, शब्बीर शाह, आसिया अंद्राबी के अलावा आलोमार मुजाहिदीन के चीफ कमांडर मुस्ताक जरगर उर्फ लत्राम, हिज्ब के टॉप ऑपरेशनल कमांडर बशीर अहमद , और लश्कर-ए-तोइबा के कई बड़े टॉप कमांडर्स और श्रीनगर के हुर्रियत ऑफिस पर भी कार्रवाई हुई है।

कार्रवाई से आतंकवाद और टेरर फंडिंग पर लगी रोक इसके अलावा आतंकियों की मदद और उन्हें शरण देने के आरोप में श्रीनगर पुलवामा अनंतनाग शोपियां कुलगाम में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने दर्जनों प्रॉपर्टीज को अटैच किया है। यह सारी कार्रवाई NIA और SI की तरफ से की जा रही है। सरकार का दावा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद-अलगाववाद पर हो रही इस कार्रवाई से न सिर्फ आतंकवाद के ग्राफ में कमी आई है बल्कि टेरर फंडिंग पर भी रोक लगी है।

विश्व बैंक द्वारा तैयार जी20 दस्तावेज़ में भारत की प्रगति की सराहना की गई



डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) का भारत पर परिवर्तनकारी प्रभाव रहा है, जिसका दायरा समावेशी वित्त से कहीं आगे तक है। विश्व बैंक द्वारा तैयार वित्तीय समावेश के लिए जी20 वैश्विक साझेदारी दस्तावेज़ ने केंद्र सरकार के तहत पिछले दशक में भारत में डीपीआई के परिवर्तनकारी प्रभाव की सराहना की है।

दस्तावेज़ डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) परिदृश्य में केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए अभूतपूर्व उपायों और इसे स्वरूप देने में सरकारी नीति और विनियमन की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है।

वित्तीय समावेश: भारत के डीपीआई दृष्टिकोण की सराहना करते हुए विश्व बैंक के दस्तावेज़ में कहा गया है कि भारत ने केवल 6 वर्षों में ऐसी उपलब्धि हासिल कर ली है, जिसे पूरा करने में लगभग

पाँच दशक लग जाते।

जेएम ट्रिनिटी ने वित्तीय समावेश की दर को 2008 के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर पिछले 6 वर्षों में वयस्कों के लिए 80 प्रतिशत से अधिक कर दिया है, जिससे इस यात्रा की अवधि 47 साल तक कम हो गई है और इसके लिए डीपीआई को धन्यवाद दिया जाना चाहिए।

दस्तावेज़ में स्पष्ट रूप से कहा गया है, “हालांकि तेजी से आगे बढ़ने में डीपीआई की भूमिका पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन डीपीआई की उपलब्धता से जुड़े अन्य घटक और नीतियां महत्वपूर्ण थीं। इनमें, अधिक सक्षम कानूनी और नियामक व्यवस्था तैयार करने के लिए कार्यक्रम, खाता स्वामित्व का विस्तार करने के लिए राष्ट्रीय नीतियां और पहचान सत्यापन के लिए आधार का लाभ उठाना शामिल हैं।

शुरुआत होने के बाद से, खोले गए

पीएमजेडीवाई खातों की संख्या मार्च 2015 के 147.2 मिलियन से तीन गुना बढ़कर जून 2022 तक 462 मिलियन हो गई; इनमें से 56 प्रतिशत यानी 260 मिलियन से अधिक बैंक खाते महिलाओं के हैं।

जन धन प्लस कार्यक्रम कम आय वाली महिलाओं को बचत करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिसके परिणामस्वरूप 12 मिलियन से अधिक (अप्रैल 2023 तक) महिला ग्राहक हैं और समान समय अवधि में पूरे पोर्टफोलियो की तुलना में, केवल पांच महीनों में औसत बचत राशि में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अनुमान है कि कम आय वाली 100 मिलियन महिलाओं को बचत गतिविधियों में शामिल करके, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक लगभग 25,000 करोड़ रुपये (3.1 बिलियन डॉलर) जमा धनराशि आकर्षित कर सकते हैं।

रसोई गैस उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत



इस योजना का लाभ केंद्र शासित प्रदेशों की सभी राजधानियों, नॉर्थ-ईस्ट और अन्य पहाड़ी राज्यों समेत मैदानी शहरों को भी मिलेगा। मोदी सरकार के इस पहमोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, रसोई गैस सिलेंडर 200 रुपए सस्ता हुआ, सभी उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत

सरकार ने मंगलवार को महंगाई से लोगों को राहत देते हुए घरों में इस्तेमाल वाले रसोई गैस सिलेंडर (एलपीजी) के दाम 200 रुपए घटाने की घोषणा की. इसके अलावा सरकार उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में 75 लाख नए एलपीजी कनेक्शन भी देगी. सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने यहां संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में सभी लोगों के लिए एलपीजी सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम करने का निर्णय किया गया.

इसके साथ ही अब उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को कुल 400 रुपए की गैस सब्सिडी मिलेगी. उन्हें पहले से 200 रुपए की सब्सिडी मिल रही है. इस फैसले के बाद राजधानी दिल्ली में 14.2 किलो का एलपीजी सिलेंडर की लागत 903 रुपए होगी,

उज्ज्वला स्कीम का 9.59 करोड़ लोग फायदा उठा रहे हैं. 30 जनवरी 2023 तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कुल 95,870,119 कनेक्शन जारी हुए थे. वहीं Ujjwala 2.0 के तहत इसी तारीख तक कुल 16,000,000 कनेक्शन जारी हुए. इस फैसले का असर सरकारी तेल कंपनियों, एचपीसीएल, आईओसी, बीपीसीएल पर नहीं पड़ेगा क्योंकि सरकार इसके लिए अलग से 7500 करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी.

जो अभी 1,103 रुपए है. उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एलपीजी सिलेंडर अब 703 रुपए में मिलेगा. ठाकुर ने कहा कि इसके अलावा सरकार उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख परिवारों को नए एलपीजी कनेक्शन देगी. इससे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की संख्या 10.35 करोड़ हो जाएगी. उन्होंने बताया कि सरकार के इस फैसले से 33 करोड़ उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी.

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी उपयोगकर्ताओं के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए की कटौती का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि यह रक्षा बंधन के अवसर पर देश की महिलाओं के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से एक उपहार है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाने को मंजूरी दी है. उन्होंने इसरो के चंद्रयान-3 मिशन की तारीफ करते हुए कहा कि पूरा देश चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग पर इसरो को बधाई देता है. इसमें महिला वैज्ञानिकों की भूमिका बेहद अहम है.

प्रगति के पथ पर, उपलब्धि



एनएमडीसी स्टील लिमिटेड की 8वीं वार्षिक

प्रिय शेयरधारक,

मैं बहुत गर्व के साथ, आपकी कंपनी की 8वीं वार्षिक आम बैठक में आपका स्वागत करता हूँ, जो कि डिमर्जर् कंपनी के बाद पहली एजीएम है; बीएसई, एनएसई और सीएसई पर इक्विटी शेयरों की लिस्टिंग; और कंपनी के इस्पात संयंत्र का प्रचालन करके भारतीय इस्पात निमाताओं की गौरवशाली लीग में प्रवेश किया।

वैश्विक अर्थव्यवस्था मंद हो रही है, और मध्यम लेकिन लक्ष्य से ऊपर मुद्रास्फीति, वित्तीय स्थितियों में संकुचन, भू-राजनीतिक संघर्षों और भू-आर्थिक विखंडन के बीच विकास अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग हो रहे हैं। जबकि वैश्विक वृद्धि वार्षिक औसत आधार पर कैलेंडर वर्ष 2023 और कैलेंडर वर्ष 2024 दोनों में 2022 के 3.5 प्रतिशत से घटकर 3 प्रतिशत होने का अनुमान है, घरेलू आर्थिक गतिविधि में लचीलापन बना हुआ है। उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत 6.1 - 6.5% की दर से विकास करेगा।

कैलेंडर वर्ष 2022 में वैश्विक इस्पात उत्पादन 1885 एमटी था, जिसमें वैश्विक कच्चे इस्पात उत्पादन में चीन का हिस्सा ~54% हिस्सा था, इसके बाद भारत, जापान, अमेरिका और रूस का सामूहिक उत्पादन ~19% था। यद्यपि, वैश्विक इस्पात उत्पादन पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 4% (कैलेंडर वर्ष 21 में वैश्विक उत्पादन - 1962 एमटी) की गिरावट देखी गई, इसी अवधि के दौरान भारत का उत्पादन 5.5% (कैलेंडर वर्ष 21 में ~118 एमटी से कैलेंडर वर्ष 22 में ~125 एमटी) बढ़ गया। दुनिया भर के अन्य देशों की तुलना में भारत में इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत चीन के बाद सबसे अधिक दर से बढ़ रही है। भारत ने 3.5% की सीएजीआर के साथ सर्वोत्तम वृद्धि प्रदर्शित की है, जो 2018 में 70.7 किलोग्राम से बढ़कर 2022 में 81.1 किलोग्राम हो गई है, जबकि वैश्विक रूप से 0.2% की गिरावट आई है, जिसका मुख्य कारण कोविड-19 का प्रभाव है। बुनियादी ढांचे, आवास, मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर बढ़ते दबाव और बढ़ते शहरीकरण के साथ खपत में वृद्धि के कारण व्यवसायिक घरेलू इस्पात उद्योग का भविष्य सकारात्मक बना हुआ है।

भारत सरकार ने 2030 तक भारत की इस्पात उत्पादन क्षमता को 300 एमटीपीए तक बढ़ाने के लिए एक रोडमैप तैयार किया। इस विजन को पूरा करने के लिए, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक और ओडिशा जैसे खनिज समृद्ध राज्यों में ग्रीन फील्ड इस्पात संयंत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। एनएमडीसी के छत्तीसगढ़ और यहां के लोगों के



साथ लंबे समय से चले आ रहे संबंधों के सम्मान में, हमने नगरनार, छत्तीसगढ़ में 3 एमटीपीए क्षमता का ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड इस्पात संयंत्र स्थापित करने की अपनी यात्रा प्रारंभ की थी।

स्टेकहोल्डरों को अधिक लाभ प्रदान करने के इरादे से, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने अक्टूबर 2020 में एनआईएसपी को एक अलग कंपनी में डिमर्ज करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी थी।

सांविधिक प्रावधानों के अनुसार प्रक्रिया का विधिवत पालन करते हुए, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने दिनांक 6 अक्टूबर, 2022 के आदेश के तहत एनएमडीसी आयरन एंड स्टील प्लांट उपक्रम को एनएमडीसी लिमिटेड ('डीमर्ज कंपनी') से एनएमडीसी स्टील लिमिटेड ('परिणामी कंपनी') में डीमर्ज करने की योजना को मंजूरी दे दी। डिमर्ज के लिए नियत तारीख 1 अप्रैल, 2021 थी और योजना 13 अक्टूबर, 2022 से प्रभावी थी।

डीमर्ज कंपनी, एनएमडीसी ने अपने शेयरधारकों को 1:1 के अनुपात में इक्विटी शेयर जारी किया जिससे उनकी अंतर्निहित संपत्ति में वृद्धि हुई। इन इक्विटी शेयरों को एनएसई, बीएसई और सीएसई पर सूचीबद्ध किया गया था और 20 फरवरी, 2023 से डीलिंग के लिए स्वीकार किया गया था। तदनुसार, आपकी कंपनी, जो पहले एनएमडीसी की एक सहायक कंपनी थी, रु. 2,930 करोड़ इक्विटी के साथ एक सूचीबद्ध कंपनी में परिवर्तित हो गई।

कंपनी ने 31 मार्च 2023 तक अपना व्यावसायिक उत्पादन शुरू नहीं किया था, इसलिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कोई लाभ/हानि घोषित नहीं की गई थी। हालांकि, प्रबंधन, कर्मचारियों और श्रमिकों के दृढ़ संकल्प और प्रशासनिक मंत्रालय तथा एनएमडीसी प्रबंधन के निरंतर सहयोग के फलस्वरूप इस्पात संयंत्र ने निम्नलिखित उपलब्धियां हासिल की:

एनएसएल ने अपनी कोक ओवन बैटरी 1 को 28 अक्टूबर 2022 को और कोक ओवन बैटरी 2 को 24 अप्रैल 2023 को चालू किया। 7 मीटर लंबी और 67 ओवन वाली दोनों कोक ओवन बैटरियां समग्र रूप से वार्षिक 1.76 एमटी कोक का उत्पादन कर सकती हैं।

एनएमडीसी आयरन एंड स्टील प्लांट, पोस्ट-नगरनार, जिला-बस्तर, छत्तीसगढ़-494001 | सीआईएन: U2

नोट: उपरोक्त कथन का तात्पर्य 07.09.2023 को आयोजित एनएमडीसी स्टील लिमिटेड की 8वीं एन

प्रायों के साथ

5 आम बैठक

हमारे इस्पात संयंत्र भारत की दूसरी सबसे बड़ी मात्रा की ब्लैस्ट फर्नेस, 4500 क्यूबिक मीटर, पॉल वर्थ टॉप चार्जिंग सुविधा के साथ स्थित है। स्थानीय देवी के नाम पर, मां दंतेश्वरी ब्लैस्ट फर्नेस को 12 अगस्त 2023 को प्रज्वलित किया गया और एनएमडीसी इस्पात लिमिटेड से हॉट मेटल का उत्पादन 15 अगस्त 2023 को शुरू हुआ था। इस्पात उत्पादन की ओर बढ़ते हुए, देश की सबसे बड़ी ब्लैस्ट फर्नेस में से एक की शुरुआत के साथ अंतिम कमीशनिंग के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है।

इसके तुरंत बाद, 21 अगस्त 2023 को स्टील मेल्टिंग शॉप का प्रचालन शुरू किया गया। इस स्टील मेल्टिंग शॉप में ऑक्सीजन की खपत को कम करने के लिए संयुक्त ब्लोइंग सुविधा के साथ दो कन्वर्टर; ब्लोइंग समय और प्लवक्स खपत को कम करने के लिए दो हॉट मेटल डिसल्फराइजेशन स्टेशन; तापमान बढ़ाने और पिघली हुई धातु की रासायनिक संरचना को समायोजित करने के लिए दो लेडल रिफाइनिंग भट्टियां; और उच्च ग्रेड स्टील के उत्पादन को सक्षम करने के लिए एक आरएच डेगैसर शामिल हैं।

इस्पात संयंत्र के थिन स्लैब कैस्टर की शुरुआत 24 अगस्त 2023 को ऊर्जा खपत को कम करने के लिए हॉट स्ट्रिप मिल में टनेल फर्नेस के माध्यम से पतले स्लैब की 100% हॉट चार्जिंग सुविधा के साथ हुई। इस संयंत्र को भारत सरकार के सतत इस्पात उत्पादन के परिकल्पना के अनुरूप, देश के सबसे अधिक ऊर्जा कुशल तथा पर्यावरण के प्रति जागरूक इस्पात संयंत्रों के रूप में डिजाइन किया गया है।

एनएमडीसी इस्पात लिमिटेड ने हॉट मेटल के उत्पादन के केवल 9 दिन बाद 24 अगस्त 2023 को अपना अंतिम उत्पाद - एचआर कॉइल का उत्पादन किया। इस्पात निर्माण क्षेत्र में पूर्व में कोई अनुभव न रखने वाली खनन कंपनी की यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी।

एक बार पूरी तरह से चालू होने पर संयंत्र एचआर प्लेट्स, एपीआई - 5 एल, क्वालिटी प्लेट्स, एचआर शीट्स, एचआर कॉइल्स, हाई कार्बन स्टील, सिलिकॉन स्टील और ऑटोमोटिव स्टील जैसे उत्पादों की एक प्रभावशाली श्रृंखला का उत्पादन करेगा। एनएसएल की सत्यनिष्ठा और इस्पात गुणवत्ता इस परियोजना पर प्रत्येक व्यक्ति की कड़ी मेहनत को बयां करेगी।

बोर्ड की ओर से, मैं प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार, एनएमडीसी प्रबंधन, मेकॉन और हमारे प्रौद्योगिकी प्रदाताओं - बीएचडीएल, टाटा प्रोजेक्ट्स, प्राइमटल्स, डेनिएली कोरस, थर्मैक्स, बीईसी और लिडे को कंपनी को उनके अटूट सहयोग के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ, जिसने एनएसएल को मजबूती से आगे बढ़ने में सक्षम बनाया है। यह उपलब्धि भारत के इस्पात निर्माताओं - सेल, जेएसडब्ल्यू और जेएसपीएल के सहयोग के बिना संभव नहीं होती, जो इस्पात संयंत्र की कमीशनिंग में हमारे साथ खड़े रहे।

मैं इस कार्य में निरंतर सहयोग के लिए कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, सेबी, बीएसई, एनएसई और सीएसई, शेयरधारकों, बैंकों, ऋणदाताओं, लेनदारों का भी आभारी हूँ। बोर्ड कंपनी के कार्यबल के समर्पण और संयंत्र के प्रचालन में उनके द्वारा दिखाए गए विश्वास और प्रतिबद्धता की सराहना करता है।



अमिताभ मुखर्जी
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)

मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि एनएसएल में ग्रांस कोक, हॉट मेटल, पिग आयरन, लिक्विड स्टील और एचआर कॉइल का उत्पादन तय कार्यक्रम के अनुसार किया जा रहा है और आगे की योजना भी तैयार है।

एनएमडीसी स्टील प्लांट एक आधुनिक परिष्कृत 3 एमटीपीए क्षमता वाला एकीकृत इस्पात संयंत्र है, जिसमें 23,840 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत पर केवल 1800 एकड़ भूमि का उपयोग करते हुए एक कॉम्पैक्ट लेआउट है। हम जिस गति से आगे बढ़े हैं, अपने सभी हितधारकों के सहयोग के साथ, हम इस्पात संयंत्र को पूर्ण क्षमता के साथ चलाने के लिए तैयार हैं, ताकि हमारे सभी हितधारकों को लाभ प्रदान किया जा सके और भारत के लिए इस्पात का सुस्थिर उत्पादन किया जा सके।

जय हिन्द !

अमिताभ मुखर्जी

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)

दिनांक: 07.09.2023

स्थान: हैदराबाद

7310CT2015G0I001618 | <https://nmdcsteel.nmdc.co.in>

एनएम की कार्यवाही का रिकॉर्ड नहीं है।



जन स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं के विस्तार के वर्ष



साल 2018

अब

900	हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर	5,372
5,186	उप-स्वास्थ्य केंद्र	5,208
785	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	796
6	शासकीय मेडिकल कॉलेज	11
36	शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	52
0	हमर अस्पताल	4
76.40%	शिशुओं के पूर्ण टीकाकरण का कवरेज	79.70%
221 प्रति लाख	मातृ मृत्यु दर	137 प्रति लाख
36.91%	कुपोषण दर	31.30%
2.63	मलेरिया एपीआई दर	0.92
204	शासकीय अस्पतालों में वेंटिलेटर	1,397
8,637 NHM	नई भर्तियां	13,467 NHM
6,835 (NHM) (2004-2018)	स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत मानव संसाधन	7,752 (NHM) (2019-2023)
61,39,487	शासकीय एवं अनुबंधित निजी चिकित्सालयों में निःशुल्क इलाज के लिए पात्र परिवार	72,65,000
30 हजार रु (राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना)	बीपीएल श्रेणी के परिवारों के लिए सालाना निःशुल्क इलाज की सीमा	5 लाख रु तक (डॉ खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना)
30 हजार रु (मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना)	एपीएल श्रेणी के परिवारों के लिए सालाना निःशुल्क इलाज की सीमा	50 हजार रु तक (डॉ खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना)
0	गंभीर और दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता	25 लाख रु तक (मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना)
0	कैंसर पीड़ितों के लिए निःशुल्क कीमोथेरेपी की सुविधा (दीर्घायु वार्ड) वाले जिला अस्पताल	17
0	किडनी रोगों से पीड़ितों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा	28 (22 जीवन धारा एवं 6 न्यास/जीवन दीप समिति मद से)



श्री भूपेश बघेल
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़



- ❖ दुर्गम क्षेत्रों और बस्तियों में 1.69 करोड़ लोगों की जांच और निःशुल्क उपचार
- ❖ श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर में 72% तक की छूट पर दवाइयां, 74 लाख लोगों को मिली राहत
- ❖ देश की सबसे अधिक आर्थिक सहायता देने वाली मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 25 लाख रु तक की आर्थिक सहायता